HVS/Lib/9 12/12/97

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

6 मार्च, 1997

खण्ड 1, अंक 2

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh * LIBRARY

विषय सूची

वीरवार, 6 मार्च, 1997

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1) 1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(1)16
स्थगन प्रस्तावों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों आदि की सूचनाएं	(1) 20
गैर सरकारी प्रस्ताव —	
आगरा कैनाल का प्रशासनिक नियंत्रण अपने अधिकार में लेने तथा हरियाणा राज्य का पानी का हिस्सा बढ़ाने संबंधी।	(1) 26

मूल्य :

Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Haryana * Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 6 मार्च, 1997

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छतर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान अब सवाल होंगे।

Completion of Harijan Chaupals

*195. **Shri Dev Raj Dewan :** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the Harijan Chaupals of following villages of Sonipat District are incomplete :—

(i) Sandal Kalan
(ii) Tharu Uledpur
(iii) Panana
(iv) Mahara
(v) Khirajpur Majra
(vi) Sandal Khurd
(vii) Badwasani

(b) if so, the time by which the aforesaid Chaupals are likely to be completed ?

Development Minister (Shri Kanwal Singh) :

(a) It is correct that Harijan Chaupals of all these villages except Sandal kalan are incomplete. The construction of the Harijan Chaupal of Sandal Kalan has been completed.

(b) No request for funds for completion of these chaupals has been received from the villages. Therefore, the time frame for their completion cannot be indicated.

श्री देव राज दीवान : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे यह महसूस करते हैं कि उनका इस सवाल का जवाब ठीक है? क्या सदन इस सवाल के जवाब से सहमत है?

श्री अध्यक्ष : आप इस बारे में मंत्री जी से पूछें।

श्री देवराज दीवान : सर, मैं मंत्री जी से ही आपके माध्यम से पूछ लेता हूं कि सोनीपत जिले में कितने गांव में हरिजनों की चौपालें अधूरी पड़ी हैं और क्या वजह है कि अभी तक इन चौपालों को पूरा करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया ?

श्री कंवल सिंह : स्पीकर सर, कितनी हरिजन चौपालें सोनीपत जिले में अधूरी हैं यह तो मैं इस समय नहीं बता पाऊंगा लेकिन मैं इनको यह अवश्य बताना चाहूंगा कि सोनीपत जिले में हमने 202 हरिजन चौपालों को बनवाने के लिए ग्रांटस दी हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, इन चौपालों को पक्का करने के लिए, कम्पलीशन करने के लिए कुछ ग्रांट्स तो सोशल वैलफेयर डिपार्टमैंट की हैं और कुछ एस०सीज० वैलफेयर डिपार्टमैंट की हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि जो चौपालें अभी अधूरी हैं उनकी कम्पलीशन कराने की राशि अब कितनी है और क्या अब यह राशि इंक्रीज हो गयी है क्योंकि अब तो पहले के मुकाबले महंगाई भी बहुत बढ़ गयी है ? इसके अलावा मंत्री जी ये भी बताएं कि इनके लिए आपके जो अपने फंडज हैं उनको आप पूरा मानते हैं और क्या आपने इन हरिजन चौपालों को पूरा करवाने के लिए सोशल वैलफेयर डिपार्टमैंट से कोई टाईअप किया है ?

श्री कंवल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिनके तहत इन चौपालों को पूरा करने के लिए राशि दी जाती थी वह तीन स्कीम्ज हैं। ये हैं — हरिजन चौपाल सबसिडी स्कीम, हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट फंड स्कीम जो कि अभी आयी है और तीसरी स्कीम डिसक्रिशनरी ग्रांट है जिसके तहत इन चौपालों को ग्रांट दी जाती है। सोशल वैलफेयर डिपार्टमैंट के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके तहत इन चौपालों को पूरा करने के लिए ग्रांट दी जाती हो। (विज) अध्यक्ष महोदय, पहले 1977 में दस हजार और पांच हजार की स्कीम थी लेकिन बाद में 1993-94 में इसको बढ़ाकर बीस और दस हजार रुपये कर दिया गया है यह स्कीम चौपालों को बनाने व पूरा करने के लिए थी लेकिन इस सरकार ने आने के बाद 1996-97 से इस राशि को बढ़ाकर सवा लाख नयी चौपालों को बनाने के लिए 50 हजार बन रही चौपालों को पूरी करने के लिए और 25 हजार रुपये उनकी रिपेयर के लिए दिया है।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ) : अध्यक्ष महोदय, मै इस बारे में कुछ बताना चाहूंगा। सर, नयी चौपाल बनाने के लिए सवा लाख रुपये निर्धारित किए गये हैं और जो चौपालें अधूरी हैं उनके लिए पचास हजार रुपये रखे गये हैं तथा इनकी रिपेयर के लिए पच्चीस हजार रुपये रखे हैं। पहले यह अमाउंट बहुत कम था जिसकी वजह से ये चौपाल पूरी नहीं हो पाती थीं। लेकिन अब यह ग्रांट्स बढ़ा दी गयी हैं और अब तीन कैटेगरी के तहत इनको ग्रांट्स दी जाती है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, दोनों मंत्रियों में से किसकी बात सही मानें।

श्री जगन नाथ : दोनों के जवाब एक हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ इतना कहना था कि जो भी स्कीम डिस्ट्रिक्ट से आती हैं अनकम्पलीट को कमपलीट कराने की तो उसके लिए पंचायत डिपार्टमैंट यह कहकर इंकार कर देता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। जैसा मैंने बताया है कि पैसा सोशल वैलफेयर डिपार्टमैंट के पास बहुत है। मैंने यह पूछा है कि क्या आपका टाईअप है ?

श्री कंवल सिंह : सोशल वैलफेयर डिपार्टमैंट के पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो कि हरिजन चौपाल के लिए पैसा दे दे।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि राज्य में वर्ष 1996-97 में कितनी नयी चौपालें बनाई गई हैं और कितनी चौपालों की मरम्मत की गई है?

श्री कंवल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल केवल सोनीपत जिले के लिए है ये उसके बारे में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री रमेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में हल्कावाइज कितनी हरिजन चौपालों के लिए ग्रान्ट दी गई है कितनी अधूरी पड़ी हैं और कितनी चौपालों की मरम्मत की गई है उसके बारे में बिवरण दें ?

श्री कंवल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यदि ब्लौकवाइज पूछना चाहें तो बता सकता हूं।

श्री रमेश कुमार : मुढलाना ब्लौक और कथूरा ब्लौक के बारे में बता दें।

श्री अध्यक्ष : वैसे इस क्वेशचन से यह सवाल रिलेटेड नहीं है फिर भी यदि आपके पास विवरण है तो बता दें।

श्री कंवल सिंह : सर, मेरे पास ईयरवाइज और विलेजवाइज डिटेल है वह मैं बता सकता हूँ।

Canal Based Water Supply Scheme for Rewari

***204. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Minister for public Health be pleased to state—

(a) the details of the funds allocated for the construction of the Canal Based Water Supply Scheme (Village Kalaka) for Rewari City during the years 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96 and 1996-97; and

(b) the time by which the said scheme is likely to be completed ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ) :

(क) रिवाड़ी शहर के लिए नहर आधारित जल आपूर्ति योजना (गांव कालाका) के निर्माण के लिये विनिहित की गई निधियों का ब्यौरा निम्न अनुसार है :—

वर्ष	विनिहित की गई राशि (रुपये लाखों में)
1992-93	62.50
1993-94	85.00
1994-95	—
1995-96	30.00
1996-97	52.00
योग :	229.50

(ख) योजना का कार्य 30-6-96 को पूर्ण हो गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो स्कीम थी वह कितने फेज में बननी थी क्योंकि इसमें फेज-1 और फेज-2 थे और फेज 2 के तहत जो टैंक बनने थे वह बन पाए या नहीं ? मंत्री महोदय, ने अपने जबाब में यह कहा है कि यह स्कीम पूरी हो चुकी है यह अनुचित है क्योंकि इसका फेज-2 बकाया है। जो टैंक बने हैं उनकी कितनी क्षमता है और जो बनने हैं वह कितनी क्षमता के बनने हैं ?

श्री जगन नाथ : स्पीकर सर, दिनांक 8-8-89 को 3 करोड़ 47 लाख की स्कीम मंजूर हुई थी। उसमें हमने 65 लाख रुपया कम खर्च किया है। इसमें हमने ऑग्मैन्टेशन करना था और दोबारा टैंक बनाने थे। वह क्यों नहीं बनाये? इसके लिये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पहले रेवाड़ी शहर को साहबी नदी के जरिए 27 दिन में पानी मिलता था इसलिए ज्यादा पानी इकट्ठा करने के लिए टैंकों की जरूरत होती थी। लेकिन जब यह नई सरकार बनी तो नई सरकार ने रजबाहों की सफाई करने के पश्चात् टेलों तक पानी पहुंचा दिया जिसके कारण 27 दिन की बजाय रेवाड़ी शहर को 15 दिन में पानी मिलने लग गया। इसलिये जिन टैंकों की पहले जरूरत थी वह अब नहीं रही और दूसरा टैंक न बनाकर हमने लगभग 65 लाख रुपये की बचत कर ली है और जितनी जरूरत है उसके हिसाब से रेवाड़ी शहर की जरूरत को पूरा कर दिया है। आज रेवाड़ी में 110 लीटर पर व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पानी मिल रहा है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से यह प्रश्न किया है कि इस समय रेवाड़ी को पानी की कितनी आवश्यकता है और इस स्कीम के तहत कितना पानी दे रहे हैं और जितनी शहर को पानी की जरूरत है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। और जो दूसरे फेज में टैंक बनना था वह क्यों नहीं बना है और मसाणी ब्रिज से या कैनाल बेसड स्कीम के तहत जो पानी मिलना था वह क्यों नहीं मिल पा रहा है ?

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, पहले रेवाड़ी शहर को साहबी नदी से पम्पिंग सिस्टम के द्वारा पानी की सप्लाई की जाती थी। लेकिन 1989 के बाद वाटर वर्कस बनने के बाद 110 लीटर पर डे पर व्यक्ति वाटर वर्कस से कैनाल बेसड पानी टैंकों द्वारा मिलने लगा और साहबी नदी का पानी ट्यूबवैल द्वारा 70 फीसदी आबादी को मिलने लग गया है जितनी रेवाड़ी शहर की आबादी है उसमें 70 फीसदी की जो आबादी है उसमें से 110 लीटर प्रतिदिन पर व्यक्ति को पानी मिलता है। परन्तु कुछ ऐरिया ऐसा रह गया है जहां छोटी-छोटी ढाणियां बसी हुई हैं जैसे आनन्द नगर, आजाद कालौनी आदि जिनकी आबादी 12 हजार के करीब है जहां पानी की कमी है उनको जल्दी ही पानी मिलने लग जाएगा क्योंकि ये कालोनियां अन-अथोराईजड बनी हुई थी इसलिए थोड़ा टाईम लग गया। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : ये दूसरा फेज बंद क्यों कर दिया और रेवाड़ी शहर को कितने पानी की रिकवायरमैंट है। शहर को पानी क्यों नहीं मिल रहा है। इस स्कीम का पैसा जानबूझ कर क्यों कट दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठिए, मैंने आपको दो बार सप्लीमैंटरी पूछने का मौका दिया फिर भी आप बीच में बोलते जा रहे हैं। कम से कम चेयर की इजाजत तो लेनी चाहिए। आप वैसे ही बीच में खड़े होकर बोलने लग जाते हैं।

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, यह सीधी सी बात थी कि इनको जो पानी पहले 27 दिन में मिलता था वह अब 15 दिन में मिलने लग गया है, इसलिए दूसरे टैंक की जरूरत ही नहीं रही। अगर जरूरत होती तो हम जरूर बनाते हमको इससे कोई दुश्मनी थोड़े ही है। कोई दुर्भावना नहीं है।

Repair of the Building of P.H.C./C.H.C.

***210. Shri Sat Narain Lather :** Will the Minister for Health be pleased to state —

(a) whether the Government is aware of the fact that the buildings of PHC Shamlo Kalan and CHC Julana are in dilapidated condition ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid buildings are likely to be repaired ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) :

(क) जी, हाँ।

(ख) भवन की मुरम्मत वर्ष 1997-98 में आरम्भ की जाएगी।

श्री सत नारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, अभी 27 फरवरी को माननीय स्वास्थ्यमंत्री जुलाना में गए थे। वहां पर जगह की तंगी है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध है कि इसके साथ लगती सरकारी जमीन, जो बी०डी०पी०ओ० ऑफिस की है वहां से बी०डी०पी०ओ० ऑफिस को शिफ्ट करके वहां पर सी०एच०सी० बनाई जाए। इससे लोगों को सुविधा हो जाएगी।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, जुलाना में वैसे तो पहले ही सी०एच०सी० है और शामलो कलां में जमीन पंचायत की है। वहां पर ये फ्री ऑफ कास्ट जमीन हमें दिलवा दें तो हम यह अस्पताल वहां चालू करवा देंगे।

श्री सत नारायण लाठर : हम दिलवा तो दें लेकिन वहां पर जगह की तंगी है।

श्री ओम प्रकाश महाजन : वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि शामलो कलां के लिए हमने 2,93,600 रु० का एस्टिमेट तैयार करवाया है और जुलाना के लिए 2,68,000 रु० का एस्टिमेट तैयार करवाया है तथा अप्रैल से पहले पहले हम वहां पर कार्य शुरू कर देंगे।

श्री जगदीश नैयर : अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमैंटरी पूछना चाहता हूं। मेरे हल्के में बहुत से हस्पताल ऐसे हैं जहां पर अभी तक स्टाफ नहीं है। इस बारे में मंत्री जी क्या कार्रवाही कर रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हाल ही में 205 नए डाक्टरों की नियुक्ति की गई है तथा आगामी 10-15 दिन के अंदर उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। जहां कहीं भी स्टाफ की कमी है, वह सब अप्रैल के महीने तक पूरी कर दी जाएगी।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मेरे हल्के में गांव भैंसवाल में पी०एच०सी० बनी हुई है तथा गांव रूखी में पी०एच०सी० अंडर कंसीड्रेशन है। यह पी०एच०सी० वहां पर कब तक चालू कर देंगे ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इनका प्रश्न उक्त तारांकित प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम इसका सर्वेक्षण करवा रहे हैं और 5000 की आबादी तक एक सब सैंटर, 30 हजार की आबादी तक एक पी०एच०सी० और 1,20,000 की आबादी तक एक सी०एच०सी० खोलने जा रहे हैं।

श्री मनी राम : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में गांव गोरी वाला में एक सी०एच०सी० है तथा वहां पर दो डाक्टरों की पोस्टें भी स्वीकृत हैं लेकिन ये पोस्टें एक साल से खाली पड़ी हैं। इस बारे में मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहता हूं कि अप्रैल माह के अंदर अंदर जितने भी अस्पताल या पी०एच०सीज वगैरह हैं सभी जगह जहां कहीं भी स्टाफ की कमी है, पूरी कर दी जाएगी।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय , मैं एक सप्लीमैंटरी पूछना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे हल्के बादली में पी०एच०सी० का भवन बनकर तैयार हो गया है और पहले भी किन्हीं कारणों से वहां पर स्टाफ ट्रांसफर नहीं किया गया, बिल्डिंग को भी हैंड ओवर नहीं किया गया और पिछले करीबन डेढ़ दो साल से नया भवन खराब हो रहा है। बच्चों ने उसके शीशे वगैरह भी तोड़ दिए हैं। मेरे विरोधी पक्ष में होने के नाते कहीं यह भवन भी विरोधी पक्ष का ही न बनकर रह जाए। मैं लायक मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इस विरोधी पक्ष की भावना से हटकर उस नए भवन में कार्य शुरू करने की जरूरत है क्योंकि पिछले दो साल से हम देख रहे हैं, वह भवन बर्बाद हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी मनी राम जी मैंने अभी आपको सप्लीमैंटरी पूछने का मौका दिया था इसलिए आप इस तरह बैठे बैठे न बोलें। अगर आपने कोई बात पूछनी है तो खड़े होकर आप मेरे से बोलने की इजाज़त लें।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार की कभी भी कतई तौर पर यह नीति नहीं रही कि हम किसी के साथ कोई पक्षपात करें। हमारी सरकार जैनुअन काम करेगी चाहे वह विपक्ष के माननीय सदस्य का काम हो और चाहे सता पक्ष के माननीय सदस्य का काम हो। सभी के साथ बराबर इन्साफ करेंगे। हमें हमारे मुख्य मंत्री जी का यह आदेश है। हम भवनों के निर्माण पर 3 करोड़ 53 लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं जिसमें 10 होस्पीटल, 9सी०एच०सी० और 25 पी०एच०सी० की बिल्डिंग के निर्माण का काम किया जाएगा जिनमें आपकी भी शामिल है।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी कितनी सी०एच०सी०, पी०एच०सी० और आर०डी० हैं जिनके अंदर स्टाफ सरप्लस है और जिनके अंदर स्टाफ की शार्टेज है। मंत्री जी इसका जिलेवार ब्यौरा देने की कृपा करें।

श्री ओम प्रकाश महाजन : स्पीकर सर, इस समय मेरे पास पूरी स्टेट का ब्यौरा है वह मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं लेकिन यदि ये जिलेवार ब्यौरा जानना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से नोटिस दे दें।

Mr. Speaker : Krishan Lal Ji, this question does not relate to it.

श्री बलबीर सिंह : स्पीकर साहब, महम हल्के के गांव बलम्बा और गांव मोखरा की पी०एच०सीज० कई महीनों से तैयार हैं लेकिन उनमें स्टाफ नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने दो बार हाऊस में आश्वासन दिया था कि उनमें स्टाफ जल्दी भेज दिया जाएगा लेकिन उनमें आज तक स्टाफ नहीं गया है। क्या चौधरी भजन लाल जी की तरह चौधरी बंसी लाल जी भी झूठे वायदे करने लग गए हैं। उन दोनों पी०एच०सीज० में स्टाफ कब तक भेज दिया जाएगा?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले निवेदन कर दिया है कि हमारी सरकार किसी भी माननीय सदस्य के हल्के में पक्षपात की दृष्टि से काम नहीं करती चाहे वह हल्का विपक्ष का हो। हमारी सरकार निष्पक्ष रूप से काम करती है किसी के साथ पक्षपात कतई तौर पर नहीं करती। बाकी रही बात बलम्बा और मोखरा पी०एच०सीज० की हम उनको भी कंसीडर कर रहे हैं।

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा : स्पीकर साहब, कलोई की पी०एच०सी० की बिल्डिंग पिछले 5-6 साल से टूटी पड़ी है और न वहां पर स्टाफ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस पी०एच०सी० की नई बिल्डिंग बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है।

श्री ओम प्रकाश महाजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि हम 10 होस्पीटल, 9 सी०एच०सी० और 25 पी०एच०सी० की बिल्डिंगज बनाने जा रहे हैं। जिस पी०एच०सी० की बिल्डिंग ठीक नहीं है और जहां पर डाक्टर की कमी है वह हमें माननीय सदस्य लिख कर दे दें उस पर हम तुरंत कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 22 दिसम्बर 1995 को उस समय के मुख्यमंत्री मेरे गांव बौंद कलां में गए थे और उस समय उन्होंने कहा था कि बौद कलां गांव की सी०एच०सी० के लिए हमारी सरकार ने 1 करोड़ 45 लाख रुपये मंजूर कर दिए हैं। क्या वहां पर सी०एच०सी० बनाने के बारे में आपकी कोई स्कीम है ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, इस समय मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि उस समय की सरकार ने उस सी०एच०सी० के लिए 1 करोड़ 45 लाख रुपये मंजूर किए थे या नहीं। इस बारे में मैं फाइल मंगवा कर देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप फाइल देख कर सोमवार को इस बारे में बता दें।

श्री ओम प्रकाश महाजन : ठीक है जी।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने बौंद कलां गांव में सी०एच०सी० बनाने के लिए 1 करोड़ 45 लाख रुपये मंजूर भी किए थे और उस गांव को सब-तहसील भी बनाया था लेकिन इन्होंने उस सब-तहसील को तोड़ दिया और उस पैसे का भी पता नहीं कहां गया।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, अगर इनका राज फिर आ जाता तो हर गांव में हर गांव का लड़का डी०सी० लगा हुआ मिलता। (हंसी)

Brigadier Hoshiar Singh Stadium

***245 Sh. Nafe Singh Rathee :** Will the Minister for Sports be pleased to state the time by which construction work of late Brigadier Hoshiar Singh Stadium is likely to be completed ?

खेल राज्य मंत्री (श्री राम सरूप रामा) : स्वर्गीय ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम, बहादुरगढ़ का प्रथम चरण का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। बाकी का जो काम रह गया है वह अगले वित्त वर्ष में पूरा कर दिया जाएगा।

श्री नफे सिंह राठी : स्वर्गीय ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम, बहादुरगढ़ का प्रथम चरण पूरा होने के बारे में बताया कि यह पूरा हो चुका है। इस बारे में मैं सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि वहां का पूरा कार्य नहीं हुआ है। वहां पर अभी तक सिर्फ दो कमरे बने हैं। सीढ़ियां भी नहीं बनाई गई हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वहां पर अब तक कितना पैसा जो चन्दे के रूप में आया या दूसरी जगहों से आया खर्च किया गया है। साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या वहां पर बैठने के लिए सीढ़ियां बनाने का कोई प्रस्ताव है और वहां पर कितनी दर्शक दीर्घा का स्टेडियम बनाया जा रहा है ? साथ ही साथ यह भी बता दें कि वहां पर किन किन खेलों का आयोजन किया जाया करेगा।

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है उस बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इस स्टेडियम का प्रथम चरण का काम पूरा किया जा चुका है। एक सवाल यह किया कि वहां पर केवल दो कमरे बनाये गए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर कमरों के अलावा स्टेज भी बनाई गई है।सीढ़ियों का निर्माण भी किया जाना है। वहां पर अब तक एम०पी० प्रोट से 3 लाख रुपये और चन्दे के रूप में 1, 92,788 रुपये आए हैं इसके अलावा खेल विभाग ने वहां पर 50 हजार रुपया दिया है।

Income Accrued from Commercial Taxes

*** 229. Shri Krishan Lal :** Will the Minister for Commercial Taxes be pleased to state the total income accrued to the State Government from Commercial Taxes during the years 1995-96 and 1996-97, separately ?

शहरी तथा नगर योजना मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) : राज्य सरकार को वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान वाणिज्यिक करों से कुल आय अलग-अलग निम्न प्रकार से प्राप्त हुई है :—

		(रुपये करोड़ों में)
1.	वर्ष 1995-96 के दौरान वाणिज्यिक करों से प्राप्त कुल आय	1276.98
2.	वर्ष 1996-97 के दौरान वाणिज्यिक करों से प्राप्त कुल आय (31 जनवरी, 1997 तक)	1307.97

श्री कृष्ण लाल : अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि वर्ष 1995-96 के दौरान 1276.98 करोड़ और वर्ष 1996-97 में 31 जनवरी तक 1307.97 करोड़ रुपये प्राप्त हुए बताए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में फैसला आने के बाद कितनी राशि प्राप्त हुई है और केन्द्र सरकार द्वारा पैट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाने के बाद कितनी राशि प्राप्त हुई है।

सेठ सिरी किशन दास : मेरे पास अलग-अलग फिगर्ज तो हैं कि किन किन आईटम्ज पर टैक्स घटाया बढ़ाया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि टैक्स चोरी करने वालों से हमें ज्यादा पैसा वसूल हुआ है।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, पिछली सप्लीमैंट्री में मैंने एक साथ दो सवाल पूछे थे लेकिन 10.00 बजे मन्त्री महोदय ने मेरे सवाल का सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया है। अतः आपके माध्यम से मेरी गुजारिश है कि मन्त्री जी मेरे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें।

सेठ सिरी किशन दास : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मैंने दिया है। इनका सवाल यह था कि कुल कितनी आय हुई है तो मैंने इनको बताया है कि 1307 लाख रुपये की आय जनवरी तक हुई है अभी दो महीने का समय शेष पड़ा है (विघ्न) अगर ये पूरी ब्रेक-अप चाहते हैं तो उसके लिए अलग सवाल पूछें। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक स्पैसिफिक सवाल पूछा है लेकिन उस सप्लीमैंट्री का जवाब नहीं आया है (विघ्न) माननीय सदस्य का सवाल यह था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो पैसा वसूल हुआ है वह कितना है, इस बारे में मन्त्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है (विघ्न)

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि राईस शैलरों के मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पैटीशन की हुई थी उस निर्णय के अनुसार 91 करोड़ रुपये की राशि सरकार के पास जमा करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राईस शैलर के मालिकों को कहा है और इसके साथ ही वह रिट खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें पैसा सरकार के पास जमा करवाना चाहिए। राईस शैलरों के लोग माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले और लगभग 45 करोड़ रुपये उन्होंने 31 मार्च तक जमा करवाने का आश्वासन भी दिया है और पैसा जमा भी करवाया है। ऐसोसियेशन के लोगों ने 50 करोड़ के लगभग रुपया 31 मार्च तक जमा करवाने तथा बाकि रकम को किश्तों में जमा करवाने के लिए अनुरोध किया है और बाकि का पैसा किश्तों में वे लोग जमा करवाएंगे इतनी ही आमदनी इससे हुई है (विघ्न)

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो प्रभावशाली लोग हैं उनसे एक भी पैसा जमा नहीं हुआ है (विघ्न एवं शोर)

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति पैसा देने से बचा है या कोई पैसा जमा नहीं हुआ है। कुछ पैसा तो वे 31 मार्च तक जमा करवा देंगे बाकी के पैसे की किश्तें कर दी गई हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सरकार उनको एकमुश्त पैसे के लिए कहे जिससे उनका रोजगार भी मारा जाए और सरकार का पैसा भी मारा जाए। इसी बात को मद्देनज़र रख कर किश्तें की गई हैं।

Aids

*215. **Dr. Virender Pal Ahlawat** : Will the Minister for Health be pleased to state —

(a) the details of the amount of grant, if any received by the State Government for the prevention/cure of AIDS from Government of India during the year 1996-97; and

(b) whether the aforesaid grant has been fully utilised; if not, the reasons thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) :

(क) 80.00 लाख रुपये निम्नलिखित सारणी अनुसार प्राप्त हुये :—

(1) दिनांक 4 जून, 1996	25.00 लाख

[श्री ओम प्रकाश महाजन]

(2) दिनांक 7 जून, 1996 45.00 लाख

(3) दिनांक 29 जनवरी, 1997 10.00 लाख

(ख) माह जनवरी, 1997 तक 45,61054 रुपये खर्च किये जा चुके हैं। शेष राशि दिनांक 31-3-1997 तक खर्च करने की सम्भावना है।

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, ऐड्ज़ एक जानलेवा बीमारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि क्या किसी सिविल होस्पिटल में या मैडिकल कॉलेज में इस बीमारी के मरीजों के लिये कहीं बैड्ज़ का प्रावधान किया गया है, अगर हां तो उसका ब्यौरा क्या है। अध्यक्ष महोदय, यह बीमारी एक मारक बीमारी है और इसके इलाज के लिए पार्टिकुलरली एक एक्विपमैंट आता है जिसका नाम सी डी-4 है, क्या मंत्री महोदय, यह बताएंगे कि किसी सिविल अस्पताल अथवा मैडिकल कॉलेज में यह इन्स्ट्रूमेंट है या नहीं है। इसके साथ ही मेरा सवाल यह भी है कि 45 लाख रुपये की राशि जो दवाईयों पर खर्च की गई है उसमें से कितनी राशि जुवेरेडीन पर , जो कि इस बीमारी के इलाज के लिये इस्तेमाल होती है, खर्च की गई है ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है यह एक अहम सवाल है। इस बीमारी से लाखों करोड़ों लोगों की जिन्दगी खराब हुई है, भगवान करे कि यह बीमारी न फैले। अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं इनके सवाल के जवाब के साथ-साथ इस बीमारी के बारे में विस्तार से बता देता हूँ। इसकी भूमिका बता देता हूँ जिन कारणों से यह बीमारी फैलती जा रही है।

श्री अध्यक्ष : महाजन जी आप इनके सवालों का जवाब ब्रीफ में बता दें।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए से इनको यह बताना चाहूँगा कि इस बीमारी की कोई दवाई नहीं है। जब यह बीमारी लगती है तो कोई भी दवाई असर नहीं करती है और आज इस बीमारी को रोकने के लिये कोई भी दवाई बनी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 1986 के अन्दर आज के मुख्यमंत्री ही उस समय मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त तामिलनाडू में चेनाई गाँव में पहली वार एडस का पेशन्ट पाया गया और पता चला कि यह बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने रोहतक मैडिकल कॉलेज के अन्दर एड्स की रोकथाम के लिये एड्स को टैस्ट करने के लिए एक सैन्टर खोला। सारे भारत में 31 जनवरी 1997 तक 29 लाख 30 हजार 718 टैस्ट किये गये हैं और 49 हजार 883 पोजिटिव टैस्ट पाये गये हैं। सारे भारत में एक हजार के पीछे 17 पेशैन्ट एड्स से ग्रस्त पाये गये हैं और हरियाणा में एक हजार के पीछे पौने दो लोग हैं। हरियाणा के अन्दर जनवरी 1997 तक 1 लाख 34 हजार 145 टैस्ट किये गये हैं और 257 लोगों का टैस्ट पोजिटिव पाया गया। अध्यक्ष महोदय, यह टैस्ट दो दफा किया जाता है जब दूसरी दफा टैस्ट किया गया तो 257 में से 231 केस ही पोजिटिव के रह गये।

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे 3 सवालों में से एक का भी जवाब नहीं आया है। एक तो ये मेरे सवालों का जवाब दे दें। इसके अवाला मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जब हरियाणा में भी एक हजार के पीछे 17 लोग एड्स से ग्रस्त हो जाएंगे तभी ये इस बारे में कुछ ऐक्शन लेंगे या अभी लेंगे ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा जब इन्होंने खुद ही माना है कि इसकी कोई दवाई नहीं है तो यह जो पैसा खर्च हुआ है वह कहां पर खर्च हुआ है।

श्री ओम प्रकाश महाजन : आपने ठीक बात पूछी है। आज लोगों को इस बारे में जागरूक करके इस बीमारी से बचाया जा सकता है। आमतौर पर एडस कैसे फैलती है इसके मुख्यतः तीन कारण है। नं० 1 यौन प्रक्रिया से, नं० 2 एडस से ग्रस्त माँ के पेट में बच्चे को और नं० 3 किसी एड्स वाले मरीज का खून दूसरे को चढ़ाने से। इसके अलावा मेरे पास सरकार का ब्यौरा है कि यह पैसा कहां पर खर्च होता है। हमने यह पैसा 1650 डाक्टरों , 1490 नर्सिज और 976 वर्कर्ज की ट्रेनिंग पर खर्च किया इसके अलावा प्रचार करने में भी पैसा खर्च होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाएं।

श्री अनिल विज़ : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने अपना उत्तर देते हुये बताया कि यह बीमारी तीन कारणों से फैलती है। उन कारणों में से एक कारण यह बताया कि यह बीमारी ब्लड ट्रांसफयूजन से फैलती है तो क्या हरियाणा में इसको टैस्ट करने का प्रावधान है ? इसके अतिरिक्त जो प्राइवेट होस्पीटल्ज हैं वहां पर जो ब्लड ट्रांसफयूजन किया जाता है वह बिना टैस्ट के किया जाता है तो क्या उनको रोकने के लिये भी सरकार ने कोई कदम उठाया है ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि एडस को रोकने के लिये क्या कोई ब्लड टैस्ट सैंटर हैं या नहीं, मैं इनको बताना चाहूंगा कि अगर हमारे यहां पर ये ब्लड टैस्ट सैंटर नहीं होते तो हम इतने मरीजों को कैसे ढूंढ पाते। इन मरीजों को ढूंढने का तरीका तो यही है कि उनका ब्लड टैस्ट किया जाता है। सर, इस समय हमारे यहां पर 19 जगहों पर ब्लड टैस्ट किया जाता है। 17 सैंटर तो हमारे जिलों में हैं और एक एक सैंटर मिलिट्री के कैम्पस में जैसे चंडी मंदिर में एवं अम्बाला कैंट में है। जहां तक प्राइवेट होस्पीटल्ज में ब्लड टैस्ट करने की बात है तो हमारे ड्रग इंसपैक्टर या ड्रग कंट्रोलर समय समय पर अलग अलग इनकी चैकिंग करते रहते हैं और अगर इस प्रकार की बातें उनके ध्यान में आती हैं तो वे उसको संभाल लेते हैं।

डॉ० वीरेन्द्र फाल अहलावत : सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मुझे अभी एक सबमिशन और करनी है।

श्री अध्यक्ष : आप अभी बैठिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मंत्री महोदय ने कहा एड्स होने के बाद उसकी कोई दवाई नहीं है जिससे इसका इलाज किया जा सके और इसीलिये प्रिवैंटिव मैयर्ज ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। सर, यह बात इनकी सही है क्योंकि जितनी इस बारे में पब्लिक अवेयरनैस होगी उतना ही एड्स पर कंट्रोल होगा। इन्होंने इस बारे में बहुत बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए हुए हैं। मंत्री जी की जो बैकग्राउंड है वह नैतिकता की है क्योंकि ये हमारे साथ रहे हैं। वैसे तो बी०जे०पी० भाई भी नैतिकता से भरे हुए हैं। (विघ्न) सर, मैं इनसे यह जानना चाहूंगा कि ये जो होर्डिंग हैं और इन पर जो फोटो और लैंग्वेज है क्या इसके बारे में मंत्री जी को पता है या उन्होंने वह लैंग्वेज पढ़ी है ? क्या ये उस लैंग्वेज के अलावा उन होर्डिंग पर कोई दूसरी भाषा नहीं लिख सकते ताकि वह एड्स की बीमारी के प्रचार के लिये इफैक्टिव लगे। इन होर्डिंग की लैंग्वेज से ऐसा दर्शाया गया है कि यौन संबंध हों तो कोई बात नहीं लेकिन थोड़े करैक्टिव मैयर्ज में हों।

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगी कि हमने इस विज्ञापन के लिये भी एक कमेटी बनायी थी क्योंकि हमने सोचा था कि यह होर्डिंग बदले जाने चाहिएं और इनकी लैंग्वेज और इनका चित्रण थोड़ा सा परिवर्तित होना चाहिए। सर, यह काम जल्दी ही हो जाएगा क्योंकि हम भी यह मानते हैं। यह होर्डिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सैंटर से ही आते हैं लेकिन सैंटर

[डॉ० कमला वर्मा]

से इनके आने के बाद मैंने आयुक्त स्वास्थ्य निदेशन एवं मीडिया से विचार कर निर्णय किया कि इसको बदला जाना चाहिए। बीरेन्द्र जी, विश्वास रखें यह काम हो जाएगा।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : स्पीकर सर, जैसा मंत्री जी ने बताया कि एड्स को रोकने के लिये प्रिवैंटिव मैयर्ज ही ज्यादा कारगर हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस बारे में हमें जो वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन से या दूसरी जगह से जो ग्रांटस दी जाती हैं क्या वह प्रिवैंटिव मैयर्ज के लिये ही दी जाती हैं या किसी दूसरी बातों के लिये भी दी जाती हैं?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, तरीका यही है जो मंत्री जी ने बताया है कि इसका कोई ईलाज तो है नहीं। इसका ईलाज तो प्रिवैंशन ही है। होर्डिंग के बारे में जो बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि ये बदले जाने चाहिएं तो हम इनको बदलवा देंगे और इनमें सुधार कर देंगे। जहां तक प्राईवेट होस्पीटल्ज में बिना टैस्ट के ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात है इसमें तो पहले ही सख्ती हो रही है लेकिन हम इस बारे में और भी सख्ती लागू कर देंगे और प्राईवेट डाक्टर्ज के ऊपर और सख्ती बरतेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 220

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री सतपाल सांगवान, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Cutting of Trees

***254. Shri Randeep Singh Surjewala** : Will the Minister for Public Health be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the trees standing within the area of water works of the villages Dhandhlan and Barhana, District Rohtak, have been cut by the officials of the Public Health Department during the period from August 1996 to February, 1997; if so, the number thereof; and

(b) whether the trees, as referred to in part (a) above, were auctioned; if so, the total amount realised therefrom ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ) :

(क) जी हाँ, मास दिसम्बर 1996 में अवैध रूप से 110 वृक्ष काटे गये।

(ख) जी नहीं।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ये जो 110 पेड़ काटे गये यह इन्वायरमैंट प्रौटैक्शन ऐक्ट का उल्लंघन नहीं है इसके अलावा कर्मचारियों द्वारा मिसट्रस्ट किया गया अगर ऐसा है तो उन कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने इन्वारयर्मैंट प्रौटैक्शन एक्ट व इंडियन पीनल कोड की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज करे हैं या कोई प्रशासनिक कार्यवाही उनके खिलाफ की गई है यदि नहीं की गई है तो क्यों नहीं की गई है ?

श्री जगन नाथ : स्पीकर सर, इनमें जितने वृक्ष काटे गये उनके हिसाब से 7-2-97 को इनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया जो धारा 302 के तहत दर्ज किया गया।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : पेड़ काटने के लिये हत्या का मुकदमा अभी दर्ज नहीं किया जाता।

श्री जगन नाथ : मैंने ऐसा गलती से कह दिया। धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और एफ०आई०आर० नं० 44/97 दर्ज कर रखी है और उनके ऐक्सीयन, एस०डी०ओ०, जे०ई०, चौकीदार, पम्प ऑपरेटर्स ये सारे के सारे ससपैंड कर दिये हैं और पुलिस केस भी उनके खिलाफ रजिस्टर कर दिये हैं।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : स्पीकर सर, मेरी जानकारी के मुताबिक इन्वायर्नमैंट प्रौटैक्शन एक्ट के तहत कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं किया गया ? क्या उन आफीसर्ज को चार्जशीट सर्व की गई है ?

श्री जगन नाथ : दिनांक 7-2-97 को धारा 409, 109, 201 के तहत एस०डी०एम० द्वारा केस रजिस्टर किया गया है और उसके हिसाब से 3 मार्च को ये सारे के सारे ससपैंड हो चुके हैं।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : स्पीकर सर, मेरा सवाल यह है कि इन्वायरनमैंट प्रौटैक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया गया ?

Mr. Speaker : You must seek permission of the Chair first. Please take your seat.

Upgradation of Government Girls Middle School, Mayna

***255. Shri Balwant Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government Girls Middle School, Mayna (Rohtak) to High School ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : वर्तमान में विद्यालय को स्तरोन्नत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री बलवंत सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मैंने विधान सभा में दो बार इसी प्रकार के क्वेशचन दिये और दोनों बार उनका यही जवाब मिला। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यही नार्म है। किन नार्म के तहत स्कूलों की अपग्रेडिंग की जाती है ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बलबंत सिंह जी का मायना गांव है। पिछली बार इन्होंने मेरे से कहा था उसके बाद हमने मायना विद्यालय का सर्वेक्षण करवाया। इस स्तर की प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से हाई और हाई से दस दमा दो विद्यालय का दर्जा बढ़ाने की प्रक्रिया है। मायना विद्यालय में केवल सात कमरे हैं कोई कार्यालय कक्ष नहीं है, कोई विज्ञान कक्ष नहीं है, कोई स्टोर नहीं है हालांकि मायना विद्यालय के पास दो एकड़ जमीन उपलब्ध है और 310 छात्राएं पढ़ती हैं। मैं माननीय साथी से कहूंगा कि इस विद्यालय में कम से कम चार कमरों का प्रावधान करा दें तो हम इस पर विचार करेंगे।

श्री बलबंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर जितने भी स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया है क्या वह सभी नार्मस के तहत ही बढ़ाया गया है और जो स्कूल आज नार्मस पूरा करते है उनका दर्जा क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है ?

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, माननीय साथी ने यह ठीक सवाल किया है क्योंकि पिछले समय में कुछ ऐसे स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया जो कि नार्मस पूरा नहीं करते थे। परन्तु हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के 22 विद्यालयों का दर्जा नार्मस के तहत ही बढ़ाया है पहले अच्छी तरह से सर्वेक्षण कराने के बाद ही दर्जा बढ़ाया गया है।

श्री भागीराम : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो 22 स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया है वह किस-किस जिले में हैं और कौन-कौन से हल्को में हैं।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, जो 22 स्कूलों की हमारी सरकार ने दर्जा बढ़ाया है वह एक तो रोहतक जिले की झज्जर तहसील में पाटौदा है। इस गांव की आबादी दस हजार से ऊपर है और विद्यालय का भवन भी बना हुआ है। उसके बाद सिलाणी स्कूल का दर्जा बढ़ाया है और इसी तरह से जो भी दूसरे स्कूल हैं उनका अच्छी तरह से सर्वेक्षण करने के बाद ही दर्जा बढ़ाया गया है।

श्री भागी राम : आप उन गांवों के नाम तो बता दें।

श्री रामबिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं सभी स्कूलों के नाम बता देता हूं। रोहतक जिले में झज्जर तहसील में समसपुर माजरा, रैया, सिलाणी, सिलाणा, ऊंटलौडा, कोहलपुर, खेतावास और पाटौदा, भिवानी जिले में अजीतपुर, सुडाणा, जैनाबवास, गोलागढ़, सिमली, बरोला, इसरवास, पिजोखड़ा और भानगढ़ तथा महेन्द्रगढ़ में पाथेड़ा, बुडीन, कोथल कलां, बसी, महेन्द्रगढ़ और गुजरवास हैं।

श्री भागी राम : सिरसा में कितने हैं ?

श्री राम बिलास शर्मा : फिलहाल तो सिरसा में नहीं हैं। अप्रैल के बाद जो भी स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जायेगा उसमें सिरसा को भी शामिल कर लिया जायेगा।

Industrial Growth Centre, Saha

***267. Shri Anil Vij :** Will the Minister for Industries be pleased to state the time by which the proposed Industrial Growth Centre Saha, District Ambala is likely to be set up ?

उद्योग मंत्री (श्री शशिपाल मैहता) : यदि भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो इस केन्द्र पर विकास कार्य अप्रैल, 1998 तक आरम्भ हो जायेगा तब तक इस काम का सर्वेक्षण होने की संभावना है। और इसके अगले दो वर्षों में पूरा हो जाने की संभावना है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, लगभग दस वर्ष बीत गये हैं और यह परियोजना ऐसी ही लटकती आ रही है। वहां पर अभी तक केवल बोर्ड ही लगा हुआ है इण्डस्ट्रिल ग्रोथ सैन्टर के नाम पर कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह भारत सरकार से अप्रूवल कब तक मिल जायेगी और इस परियोजना के लिये वित्तीय संस्थाओं में कौन सी संस्था है जो इस परियोजना का खर्च वहन करेगी।

श्री शशिपाल मैहता : अध्यक्ष महोदय, 410 एकड़ जमीन को एक्वायर कर लिया है और जब भी भारत सरकार से अप्रूवल मिलेगी काम शुरू कर दिया जायेगा। इस परियोजना की लागत आज लगभग 30 करोड़ है और काम पूरा होने तक यह राशि लगभग 80 करोड़ तक पहुंच जायेगी।

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार से अप्रूवल प्राप्त होने के बाद इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर में क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी और कब तक कर दी जाएंगी ?

श्री शशिपाल मैहता : अध्यक्ष महोदय, जब काम शुरू होगा उसके बाद पूरी सुविधाएं जो इंडस्ट्रियल टाउन में होती हैं वह सब उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे सड़कें, पानी, बिजली, शैड, प्लाट, हर चीज वहां पर उपलब्ध कराई जाएगी।

श्री सत नारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्रोथ सैंटर का जो मामला श्री अनिल विज जी ने उठाया है, यह तो हमारा हिस्सा छीना गया है। यह ग्रोथ सैंटर तो पिछली सरकार ने जुलाना में स्थापित करने का निर्णय किया था। वहां से उठाकर के चौधरी भजन लाल की सरकार इसको साहा में ले आई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके बदले में जुलाना को कुछ देने का सरकार का इरादा है ?

श्री शशिपाल मैहता : अध्यक्ष महोदय, इसके बदले में तो ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि इससे पिछले सत्र में इसका जवाब दिया गया था क्योंकि जुलाना में ज्यादा सुविधाएं नहीं हैं जैसे मेन रोड़, व रेलवे लाईन के पास स्थित होना इत्यादि। इसके कारण ही सैंटर से स्वीकृति मिलने में कठिनाई है। इसीलिए इसको साहा में लाया गया है।

श्री सत नारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, क्या सभी विकास कार्य जी०टी० रोड पर ही होंगे क्या हमारे यहां पर कुछ नहीं होगा ?

श्री शशि पाल मेहता : वहां पर भी जरूर कुछ हो सकता है। वैसे हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर कई तरह की सुविधाएं नहीं हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से आपके हल्के के साथ ऐसा कुछ किया जा रहा है। यह पिछली सरकार ने किया था। हमने इसमें कोई नया प्रावधान नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : अगर पिछली सरकार ने कुछ किया है तो क्या आपकी सरकार इसको फिर से एग्जामिन कराएगी ?

श्री शशिपाल मैहता : अध्यक्ष महोदय, हम इसको जरूर एग्जामिन कराएंगे। लेकिन वहां पर इंडस्ट्रियल टाउन के लिए कोई हिसाब-किताब नहीं बन रहा है। फिर भी वहां पर कोई छोटा-मोटा इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का यत्न करेंगे।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर में कितनी यूनिटस लगाई जाएंगी, कितने प्लाट्स इसके बनाए जाएंगे। क्या ऐसी कोई योजना बनाई गई है?

श्री शशिपाल मैहता : अध्यक्ष महोदय, अभी टाउन बसा नहीं है और इसकी योजना पहले ही पूछ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अन्दर प्लाटों की संख्या इस प्रकार होगी — 250 गज के 35, 500 गज के 38, एक हजार गज के 34, 2 हजार गज के 30 और एक एकड़ के 36, दो एकड़ के 3, 3 एकड़ के 5, 4 एकड़ का एक।

श्री सत नारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, जब हमें ही कुछ नहीं मिल रहा है, तो दूसरों को भी क्यों मिले (हंसी)

श्री शशिपाल मैहता : अध्यक्ष महोदय, इनका मतलब तो यह है कि जुलाना में जब यह सैंटर नहीं लग रहा है तो साहा में भी न लगे (हंसी)

Imposition of Ban on State Lotteries

***203. Shri Ram Pal Majra :** Will the Minster for Finance be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to impose ban on lotteries run by Haryana Government ?

वित्त मंत्री (श्री चरण दास) : जी नहीं।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पिछली सरकार प्रतिदिन कितने ड्रा निकालती थी और आज की सरकार कितने ड्रा प्रतिदिन निकाल रही है ?

श्री चरण दास : अध्यक्ष महोदय, प्रतिदिन नौ निकाल रही है। (हंसी)

श्री अध्यक्ष : यह नौ कौन सा है ? (हंसी)

श्री चरण दास : सर, संख्या नौ (नाइन) है।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हर रोज 12 ड्रा निकाले जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न काल खत्म होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Opening of Government College at Badli

***280. Shri Dhir Pal Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a College at Badli in Rohtak District ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : जी, नहीं।

Construction of Roads

***252. Shri Nafe Singh Jundla :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads in district Karnal :—

(i) Barota to Jundla via Kheri-Naru;
(ii) Kheri-Naru to Jani;
(iii) Dadupur to Kheri-Naru;
(iv) Jundla to Jarifabad;
(v) Bansa to Pakakhera;
(vi) Katlaheri to Augandh;
(vii) Katlaheri to Jundla;
(viii) Brass to Bastali;
(ix) Gondar to Badnara; and
(x) Picholia to Jani; and

(b) if so, the time by which the aforesaid roads are likely to be constructed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मवीर यादव) :

(क) नहीं, श्री मान् जी,

(ख) उपरोक्त (क) को सम्मुख रखते हुये उपरोक्त सड़कों के निर्माण बारे कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती।

Posting of Veterinary Doctor

***196. Shri Dev Raj Dewan** : Will the Minister for Animal Husbandary be pleased to state —

(a) whether the Government is aware of the fact that there is no Veterinary Doctor in Veterinary Dispensary of Village Chatia Aulia, District Sonipat for the last two years; and

(b) if so, the time by which the Veterinary Doctor is likely to be posted in the said Dispensary ?

पशुपालन मंत्री (श्री हरमिन्दर सिंह) :

(क) तथा (ख) गांव चेतिया औलिया, जिला सोनीपत में कोई पशु औषधालय/हस्पताल स्वीकृत नहीं किया गया है, इसलिये पशु चिकित्सक लगाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Kheri Sheru Minor

***202. Shri Ram Pal Majra :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Kheri-Sheru Minor in District Kaithal; and

[Shri Ram Pal Majra]

(b) if so, the time by which the aforesaid Minor is likely to be constructed ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) :

(क) तथा (ख) जी हां, जिला कैथल में खेड़ी ..... शेरू माइनर के निर्माण की परियोजना सरकार ने वर्ष 1991 में स्वीकृत की थी। भूमि अर्जन करने का कार्य भी प्रारम्भ किया गया था, परन्तु माइनर की निशानदेही के बारे में पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में लम्बित केस के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी। इस अवस्था में इसके निर्माण की कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती।

Construction of Fly-over Bridge in Rewari

***205. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a fly-over in Rewari City; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मवीर यादव) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) पुल के स्थान नियत करने तथा इसके वित्त संसाधन व्यवस्था बारे मामला विचाराधीन है तथा रेलवे के साथ इस विषय में विचार विनिमय जारी है। अतः इस पुल के निर्माण के लिए कोई समयावधि नियत नहीं की जा सकती।

Augmentation of Water Supply Schemes

*** 211. Shri Sat Narain Lather :** Will the Minister for Public Health be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to augment the water supply schemes of Nidani, Khema Kheri and Shamlo Khurd, Rajgarh, Desh Khera, Buwana and Devrod villages of District Jind; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialised ?.

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ) :

(क) गांव निडानी, खेमा खेड़ी तथा शामलु खुर्द की जल वितरण योजना में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है।

(ख) गांव निड़ानी, खेमा खेड़ी तथा शामलु खुर्द की जल वितरण योजना में बढ़ौतरी, 31-12-1997 तक सम्पन्न कर दी जायेगी।

Auto-Market, Bahadurgarh

*246. **Shri Nafe Singh Rathee :** Will the Minister for Town & Country Planning be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Auto Market at Bahadurgarh; if so, the time by which the aforesaid Auto Market is likely to be constructed ?

शहरी तथा नगर योजना मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) : बहादुरगढ़ में आटो मार्किट बनाने के लिए प्रस्ताव है, जिसके स्थल के चयन के बारे निर्णय लिया जा रहा है। अतः इस अवस्था में इसके निर्माण के लिए निश्चित समय अवधि नहीं दर्शाई जा सकती।

Number of School upgraded in the State

*225. **Shri Krishan Lal :** Will the Minister for Education be pleased to state the districtwise number of schools, if any, upgraded from Primary to Middle, Middle to High and High to Senior Secondary in the state during the year 1995-96 and 1996-97 ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : सूचना सदन पटल पर रखी जाती है।

सूचना

क्रम	जिले का नाम	प्राईमरी से मिडल	मिडल से हाई	हाई से सीनियर सैकेण्डरी
1.	अम्बाला/पंचकूला	16	28	15
2.	भिवानी	8	16	12
3.	फरीदाबाद	8	6	10
4.	गुड़गांवा	8	9	11
5.	हिसार	27	29	22
6.	जीन्द	7	12	10
7.	करनाल	9	6	10
8.	कैथल	7	6	7
9.	कुरूक्षेत्र	6	3	3
10.	पानीपत	5	4	4
11.	नारनौल	6	3	5
12.	रिवाड़ी	3	4	6

[श्री राम बिलास शर्मा]

13.	रोहतक	11	9	10
14.	सोनीपत	13	10	12
15.	सिरसा	10	7	5
16.	यमुनानगर	6	7	7
	कुल जोड़	150	159	149

वर्ष 1996-97 में स्तरोन्नत होने वाले विद्यालयों की जिलावार सूची/संख्या

1.	भिवानी	3	6	—
2.	रोहतक	3	2	2
3.	महेन्द्रगढ़	—	3	3
	कुल जोड़	6	11	5

Opening of Blood Bank in Private Sector

*216. **Shri Virender Pal Ahlawat :** Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for opening of 'Blood Banks' in private sector in the State ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) : जी हाँ।

स्थगन प्रस्तावों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों आदि की सूचनाएं

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारी एक एडजर्नमैंट मोशन है जो हमने आपको दी हुई है। वह एक बड़ा अहम मसला है। कल पंजाब विधान सभा में पंजाब के गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में चण्डीगढ़ के मामले को उठाया। चण्डीगढ़ का मामला हरियाणा प्रदेश के हितों के साथ जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आपका दिया हुआ एडजर्नमैंट मोशन अभी अभी 9.20 बजे मेरे पास आया है।

That is under consideration. Please take your seat.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा अहम मुद्दा कोई दूसरा नहीं हो सकता। चण्डीगढ़ का मामला हरियाणा प्रदेश के हितों के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए उस एडजर्नमैंट मोशन पर हाऊस का दूसरा बिजनैस छोड़ कर डिस्कशन की जानी चाहिए।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रकाश ने जो बात कही है उनकी यह बात बिल्कुल ठीक है। हम इनकी इस बात से असहमत नहीं हैं। इस मुद्दे पर आज सरकार विचार करेगी और अगले सोमवार को सारी अपोजिशन पार्टीज के लीडर्ज को बुला कर इस पर विचार करेंगे और सब की सहमति से हरियाणा प्रदेश के हित में जो बात होगी वही करेंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या लीडर ऑफ दि हाउस इस बात का आश्वासन देंगे कि इस बारे में एक मुस्तरका प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार को भेज दिया जाएगा।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आज तो इस बारे में विचार नहीं किया जा सकता लेकिन सोमवार को इस बारे में सभी पार्टीज के माननीय नेताओं को बुला कर इस बारे में बात करेंगे और हरियाणा प्रदेश के हित के बारे में जिस बात पर सभी की सहमति होगी वही बात करेंगे। हरियाणा प्रदेश के हितों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही अहम मुद्दा है इसलिए हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर हरियाणा प्रदेश के हितों को ध्यान में रख कर सर्वसम्मति से निर्णय लेना चाहिए। क्या चौधरी बंसी लाल जी मेरी बात से सहमत होंगे क्योंकि यह मामला पहले भी हाउस में आ चुका है। इस प्रकार के मुद्दे चाहे वह कावेरी जल विवाद का हो चाहे नर्मदा का हो और चाहे बंगलौर-तामिलनाडु का मामला हो जब वे दूसरी सरकारें दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर और अपने अपने राज्य के हित को ध्यान में रखकर निर्णय ले सकती हैं तो क्या हरियाणा प्रदेश की सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती। हरियाणा प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 90 लोग यहां हाउस में बैठे हुए हैं हम सभी इस बारे में एक मुस्तरका निर्णय लें और इस बारे में एक प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार को भेजें। क्या इस बात से मुख्य मंत्री जी सहमत होंगे ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बातों का फौरी तौर पर जवाब दे दूंगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : केवल जवाब देने से ही काम नहीं चलता।

श्री अध्यक्ष : लीडर ऑफ दी हाउस ने अश्वौर कर दिया है and that must be taken seriously.

श्री अनिल विज : स्पीकर साहब, हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि वह हिमाचल प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही दूरदर्शन पर टैलीकास्ट किया करेगी। यह बात समाचार-पत्रों में आई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या हमारी सरकार भी अपनी विधान सभा की कार्यवाही दूरदर्शन पर टैलीकास्ट करने के बारे में कोई विचार करेगी।

श्री बंसी लाल : यह मामला तो स्पीकर साहब से संबंधित है।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मामला उठाया है। जो मामला इन्होंने उठाया है वह बहुत ही अहम मामला है। आपने भी पढ़ा होगा कि पंजाब के गवर्नर महोदय ने अपने ऐड्रेस में यह कहा है कि चण्डीगढ़ फौरन पंजाब को दिया जाए और हरियाणा प्रदेश में जो पंजाबी भाषी गांव हैं वे भी फौरन पंजाब प्रदेश को ट्रांस्फर किए जाएं। यह कोई छोटा मसला नहीं है यह एक बहुत बड़ा अहम मसला है। उन्होंने पानी के बारे में भी कह दिया कि पानी में हरियाणा प्रदेश का कोई हक नहीं है। इसलिए यह एक बड़ा अहम मसला है आप इस बारे में एक प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार को भेजें। पहले स्पीकर साहब, आप भी, चौधरी बंसी लाल जी और राम बिलास शर्मा जी यह कहते रहे कि इस बारे में हमें एक प्रस्ताव पास करना चाहिए। हमने इसलिए ऐसा प्रस्ताव पास करके नहीं भेजा कि यदि हम करते तो वे भी करते। (शोर)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सदन में चौधरी भजन लाल, चौटाला साहब और संयोग से आप भी उसमें विराजमान थे। उस वक्त श्री भजन लाल जी मुख्य मंत्री थे।

[श्री राम बिलास शर्मा]

उस समय हरियाणा और पंजाब से जुड़े मुद्दों पर चौधरी बंसी लाल जी ने, बी०जे०पी० ने और विपक्ष के दूसरे साथियों ने हर सत्र में आग्रह किया कि हम सब को राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा के हितों के लिये, चाहे वह राजधानी का मामला हो, चाहे वह टैरीटेरी का मामला है या पानी का मामला हो एक प्रस्ताव पास करना चाहिए। हम सबने कहा कि हम इस विषय पर सब भजन लाल जी के साथ हैं और हम आपके साथ प्रधानमंत्री के पास चलते हैं लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं सुनी। अब इस इशू पर हमारे माननीय नेता श्री बंसी लाल जी ने श्री ओम प्रकाश जी चौटाला के जवाब में और दूसरे साथियों के जवाब में कहा है कि 10-3-97 को हम सभी से बातचीत करेंगे और एक सर्वसम्मति से निर्णय लेकर कोई अंतिम निर्णय लेने के बाद जो ठीक होगा, वह करेंगे। आज ये कह रहे हैं कि हमें सर्वसम्मति से कोई प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजना चाहिये। हमारे नेता ने तो विश्वास दिलाया है कि हम सभी इस पर मिलकर विचार करेंगे लेकिन ये तो बात सुनने के लिये तैयार नहीं होते थे। (विघ्न) हमने उस बार एक बार नहीं 3-3 बार कहा कि एक प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजना चाहिए लेकिन इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं।

श्री भजन लाल : आप मेरी बात सुनिये। उस वक्त पंजाब विधान सभा में ऐसी कोई बात नहीं आई थी, जो कल वहां पर गवर्नर महोदय के अभिभाषण में आई थी। इसलिये अब यह इशू और महत्वपूर्ण हो गया है।

श्री राम बिलास शर्मा : अब आप कह रहे हैं कि उस वक्त ऐसी बात नहीं आई थी। हमने हर बार कहा कि कोई प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजना चाहिये। (शोर)

श्री भजन लाल : मैं यह कह रहा हूं कि जो बात अब वहां पर पंजाब विधान सभा में आई है वह उस वक्त नहीं आई थी। (शोर) अब वहां पर अकाली और बी०जे०पी० का गठजोड़ है इसलिये प्रस्ताव पास नहीं करना चाहते।

श्री राम बिलास शर्मा : अकाली और बी०जे०पी० का डंके की चोट का गठजोड़ है उन्होंने यानि वहां की बी०जे०पी० ने अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है।

श्री अध्यक्ष : मैं पहले सदन को बताना चाहता हूं कि किन-किन लोगों के काल अटैंशन मोशन और एडजर्नमैंट मोशन आए हैं, और उस पर क्या निर्णय लिया गया है। (विघ्न) पहले मैं अपनी बात कह लूं, उसके बाद फिर अपनी बात कहें।

Mr. Speaker : Please take your seat. Let me tell the fate of the motions. I have received a Motion under Rule 66 from Shri Om Parkash Chautala and 15 other M.L.As regarding spreading up of Pilia disease in the District of Sirsa in Haryana. That has been converted into calling attention motion and has been admitted for 10th March, 1997. The second adjournment motion is from Sh. O. P. Chautala regarding privatisation of Haryana State Electricity Board. That is under consideration. The next calling attention motion is from Capt. Ajay Singh and Rao Narender Singh M.L.As regarding six feet high wall on the out-let of the Massani Barrage which has been sent to the Government for comments. The next calling attention motion is also from Capt. Ajay Singh and Rao Narender Singh M.L.As regarding abolition of slab system on the rate of power tariffs on the tubewells in the districts of Rewari and Mahindergarh which has been disal-

lowed. The next calling attention motion is also from Capt. Ajay Singh and Rao Narender Singh, M.L.As regarding sewerage water entered in the villages of Naya Gaon, Dolatpur and Dabri etc. in district Rewari. It has been sent to Government for comments. The next calling attention motion is also from Capt. Ajay Singh and Rao Narender Singh, M.L.As regarding flow of chemical poisonous water from Industrial Estate, Bhiwani. It has also been sent to Government for comments.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ट्यूबवैल्ज पर पावर टैरिफ का यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है लेकिन आपने इसको डिसअलाऊ कर दिया है। इसे डिसअलाऊ करने का आपने कोई भी कारण नहीं बताया है। मेरी गुजारिश है कि आप अपने फैसले पर पुनः गौर फरमाएं। (विघ्न एवं शोर)

Mr. Speaker : Capt. Ajay Singh, you please take your seat. (Interruptions). Capt. Sahib, that has been disallowed. You please take your seat. If you will speak like this, you would not be permitted (Interruptions).

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जो यह मुद्दा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है (विघ्न एवं शोर), आप मेरी बात सुनिए। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठिये। (विघ्न एवं शोर)

Hon'ble members next is a notice of calling attention motion from Shri Dhir Pal Singh, M.L.A. regarding non-supply of electricity and bogus bills in Badli constituency. It is under consideration. Dhir Pal Singh Ji, your second notice of calling attention motion is regarding transfer of powers of R.T.As to Executive Magistrates which is also under consideration.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में मेरा भी एक कॉलिंग अटैंशन मोशन था, उसका आपने कोई ज़िक्र नहीं किया है, कृपया यह बताइये कि उसका क्या फेट हुआ ?

श्री अध्यक्ष : वह आज ही आया है और अण्डर कंसिडेशन है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सिरसा में फैली बीमारी के बारे में मैंने एडजर्नमैंट मोशन दिया है जिसे कि आपने कालिंग अटैंशन मोशन में कन्वर्ट कर दिया है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की कृपा करें। यह मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा है क्योंकि यह मामला इन्सानी जानों के साथ जुड़ा हुआ है। अभी तक इस बीमारी के कारण 19 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। यह भी आशंका है कि यह बीमारी वहां पर भयंकर रूप ले ले और मेधात जैसी स्थिति वहां पर भी उत्पन्न हो जाए। हमें यह अंदेशा है कि अगर यह बीमारी अधिक फैल गई तो सरकार इसे काबू करने में विफल हो जाएगी। यह इंसानी जानों से जुड़ा हुआ मसला है इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे एडजर्नमैंट मोशन के रूप में ही लिया जाए। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार के पास इस बारे में रिपोर्ट है कि यह बीमारी किस-किस गांव में फैली हुई है। इसलिए मैं आपसे फिर पुरज़ोर अपील करूंगा कि इस मामले को कॉलिंग अटैंशन मोशन की बजाए एडजर्नमैंट मोशन के रूप में लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आपकी इस एडजर्नमैंट मोशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसे कॉलिंग अटैंशन मोशन में कन्वर्ट कर दिया गया है।

Chautala Sahab, I would like to draw your attention to page 451 of the

[श्री अध्यक्ष]

book Practice and Procedure of Parliament by Kaul and Shakdher, which says :-

> "It has been held that an adjournment motion on a matter which can be raised during debate on the motion of thanks on the President's/Governor's Address, budget discussion, motion on international situation, motion regarding a matter of public importance such as food policy, etc. to be held in the same session is not in order. Similarly a matter which can be raised under any other procedureal device viz calling attention notices, questions, short notice questions, half and hour discussion, short duration discussion etc. cannot be raised through an adjournment motion."

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात से सहमत हूं लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इस में रूल्ज़ और कानून का दखल नहीं होना चाहिए क्योंकि यह मसला इन्सानी जानों से जुड़ा हुआ मसला है। आपका जो भी निर्णय होगा वह तो मान्य होगा ही। आपके निर्णय को न मानने का परिणाम तो मैं पहले भुगत चुका हूँ और आईन्दा इस प्रकार के परिणाम भुगतना नहीं चाहूंगा (हंसी) इसलिए आपसे निवेदन है कि इस पर दोबारा से गौर फरमाएं।

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Speaker, Sir, the Government is fully aware of the situation and whatever steps should be taken, they are being taken by the Government and a detailed reply will be given on the motion which has been admitted by you. The Health Minister was telling me in the morning that he would be going in the area today afternoon alongwith the team of doctors. Now I am told that a team of doctors has already been sent to the area and medicines will also be imported. Orders for medicines have already been placed as the medicines were not available.

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी आप बोलना चाहते हैं तो बोलें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम फुल्ली अवेयर हैं। अगर यह सरकार फुल्ली अवेयर है तो इस बारे में डिस्कशन करने में क्या हर्ज है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला तो यह चाहते हैं कि रूल्ज को स्क्रैब कर दो और जिस तरह से ये कहें उसी तरह से हाउस को चलाएं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाएं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से भागीराम जी इस बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि यह उनके क्षेत्र से रिलेटिड मामला है।

Mr. Speaker : Chautala ji, the adjournment motion has been converted into calling attention motion. You will get ample oppourtunity to speak. Now the matter ends. (विघ्न) पहले भजल लाल जी को बोलने दिया जाए।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी और नारनौल में ट्यूबवैल्ज़ के बिजली के फ्लैट रेट एक जैसे कर दिए हैं। इस सरकार ने इनके रेट दूसरे एरिए के साथ बराबर कर दिए हैं। जबकि वहां पर पानी बहुत नीचे हैं। दूसरे एरियाज़ में पानी दो-अढ़ाई इंच का पाईप चलता है इन तीन एरियों में 80-90 फुट नीचे हैं। दूसरे एरियाज़ में एक एकड़ भूमि एक घंटे में गीली हो जाती है और इन तीन एरियाज़ में चार-पांच घंटे में भी जमीन एक एकड़ गीली नहीं होती है। इस बात को लेकर कैप्टन

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

अजय सिंह और रणदीप सिंह ने काल अटेंशन मोशन दिया था जोकि आपने रूल्ड आउट कर दिया है। आप इस बारे में दोबारा से विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष : यह आलरेडी डिसअलाउ हो चुका है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट आफ आर्डर पर बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में जो भी बात कही जानी हो या कही जाए वह आपकी इजाजत से और आपको एड्रैस करके कही जानी चाहिए। लेकिन रूलिंग पार्टी के मैम्बर पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर और सांगवान जी आपकी इजाजत लिए बिना, खड़े होकर आपको एड्रैस किए बिना ही बोलने लग जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मान सकता हूँ कि सांगवान जी नए आए हैं इनको इस बात का ज्ञान नहीं है लेकिन जो पुराने हैं उनको तो इस बात का पता है (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, क्या ये आपकी इजाजत के बिना सीधे बात कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, कल भी आपने गौर से देखा होगा जब मैं राज्यपाल अभिभाषण का प्रोटैस्ट करते हुए बोल रहा था तो सांगवान जी राज्यपाल जी को खड़े होकर सलाह दे रहे थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सांगवान जी आप बैठ जाएं। कैप्टन साहब आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) आप सब बैठ जाएं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरी एडजर्नमैंट मोशन थी मैं उस बारे में बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : मैंने उस बारे में बता दिया है आपने सुना नहीं है। आप अपने कान खुले रखें।

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बोलते हुए मेरा नाम लिया कि पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर बीच में बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन में सभी सदस्यों का फर्ज है कि वह सदन में नियमों की पालना करें। अध्यक्ष महोदय, कल से आपकी अध्यक्षता में यह सदन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आप जब भी कोई रूलिंग देते हैं तो ओम प्रकाश जी उसको न मानते हुए अपनी बात कहनी शुरू कर देते हैं यह देखकर हमें बहुत दुःख होता है। अध्यक्ष महोदय, भजन लाल जी मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया है फिर भी बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूँ कि ये आदरणीय सदस्य हैं इसलिए इनको सदन की गरिमा को मानना चाहिए और जो नियमों में लिखा हुआ है उसके अनुसार ही इनको अपनी बातें कहनी चाहिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपकी बात मान रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह तो गनीमत है कि पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर इस बात को अगर मानें कि सदन की गरिमा को बनाकर रखा जाए। हम तो इस बात के पक्षधर ही हैं। मैंने तो यही कहा था कि अगर कोई भी सदस्य आपकी अनुमति से बोल रहा है तो उस समय दूसरे किसी सदस्य को इंटरवीन नहीं करना चाहिए और अगर वह इंटरवीन करें तो उसे आपकी इजाजत लेनी चाहिए। पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर एवं सांगवान साहब को यह अधिकार नहीं कि वे बीच में ऐसे ही बोलने लगें। ये हमें अपने अधिकार की उल्लंघना करते हुए धमकाने की कोशिश करते हैं। (विघ्न)

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, आप इनसे पूछिए कि इनको कौन धमका सकता है इन्होंने तो सारी उम्र और लोगों को धमकाया ही है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप इनको एक बात समझा दें कि लंका में सभी 52 गज के हैं। इस सदन में सभी सम्मानित सदस्य हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अब आप सभी बैठिए और श्री भागीराम जी को बोलने दें।

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत : सर, मेरी एक सबमिशन है कि किसी भी सदस्य को बोलने से पहले आपको ऐड्रस करना ही जरूरी नहीं बल्कि आपसे परमिशन लेना भी जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : यह बात आप पर भी लागू होती है।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, क्या अब इन्होंने आपसे परमिशन ली है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठें और भागी राम जी को बोलने दें।

श्री भागीराम : अध्यक्ष महोदय, काम की एक बात नहीं हो रही है। मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूँ कि जोहतड़, सुल्तानपुरिया, ऐलनाबाद, रानिया, गीदड़ावाली, बेहरवाला, तरीवाला इत्यादि गांवों में जो कि सिरसा जिले में पड़ते हैं, के गांवों के आदमी पीलिया की बीमारी की वजह से मर रहे हैं और सैंकड़ों आदमी अभी भी अस्पतालों में पड़े हुए हैं। मंत्री जी तो सरकारी अस्पतालों का रिकार्ड बता रहे हैं जबकि प्राईवेट अस्पतालों में जो बीमार लोग दाखिल हैं उनका इनको पता ही नहीं है। आज वहां पर इस बीमारी के कारण बहुत बुरा हाल है। अध्यक्ष महोदय, वहां के एक गांव में जब इनका एक वजीर जाता है तो उसने गांव में जाकर लोगों से इस बीमारी की बात पूछने के बजाए यह पूछा कि दारू बंद हुई है या नहीं। गांव वाले मंत्री से बोले कि हम तो मर रहे हैं और आपको दारू की लगी हुई है। आज वहां पर लोग अपना-अपना काम छोड़ने को मजबूर हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले को आप यहां पर जल्दी ही डिसकशन करवाएं। इसमें किसी को क्या आफत आ रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जो कुछ भावनाएं अभी यहां पर इस बारे में व्यक्त की गयी हैं और चूंकि यह बहुत ही सीरियस मैटर है इसलिए इस मामले पर डिसकशन के लिए दस तारीख निश्चित की गयी है अतः आप उस दिन पूरी जानकारी इस मामले में सदन को दें।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) : ठीक है जी।

गैर सरकारी प्रस्ताव

आगरा कैनाल का प्रशासनिक नियंत्रण अपने अधिकार में लेने तथा हरियाणा राज्य का पानी का हिस्सा बढ़ाने संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a non-official resolution regarding taking over the administrative control of the Agra Canal passing through the Haryana Territory and also to increase the share of water of Haryana State. Now, Shri Jagdish Nayar may move his resolution.

श्री जगदीश नैयर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि —

यह सदन राज्य सरकार से सिफारिश करता कि वह हरियाणा क्षेत्र से गुजरने वाली आगरा नहर का प्रशासनिक नियंत्रण अपने अधिकार में लेने तथा हरियाणा राज्य का पानी का हिस्सा बढ़ाने संबंधी मामला उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाएं।

Mr. Speaker : Motion moved -

This House recommends to the State Government to take up with the Uttar Pradesh Government the matter regarding taking over the administrative control of the Agra Canal passing through the Haryana Territory and also to increase the share of water of Haryana State.

श्री जगदीश नैयर (हसनपुर अनुसूचित जाति) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से आगरा कैनाल के बारे में जानना भी चाहता हूँ और अपनी बात भी कहना चाहता हूँ। यह हरियाणा प्रदेश के किसानों के दु:ख-दर्द का मसला है। आगरा कैनाल का सवाल तब का है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से यह मसला उठ रहा है लेकिन आज तक किसी सरकार ने इस पर कब्जा नहीं किया। मैं हृदय से मुख्य मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने अपने सात महीने के कार्यकाल में हमारे सात रजवाहों को उत्तर प्रदेश सरकार से अपने कब्जे में ले लिया है जिसका फायदा हमारे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के किसानों को होगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो किसान हैं आज सी०एम० साहब के लिए आंखें बिछाये बैठे हैं जो काम पिछले 20 सालों में नहीं हुआ था वह काम इस सरकार ने सात महीने में कर दिखाया है। अगर कोई विपक्षी भाई इसे गलत कहते हैं या समझते हैं तो वे मेरे साथ चलें मैं उनको वहां जाकर दिखा सकता हूं कि वहां पानी टेल-टू-टेल पहुंचा हुआ है। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूँ (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) कि हमारी सरकार ने सात रजवाहों को तो अपने कब्जे में ले लिया है लेकिन कुछ रजवाहे और भी हैं जिनको कब्जे में लिया जाना जरूरी है जिससे हमारे हरियाणा प्रदेश के मेवात क्षेत्र के लोगों का हित जुड़ा हुआ है। अभी मेरे हसनपुर क्षेत्र के रजवाहे भी रह गए है वे रजवाहे भी इसमें जुड़वाने का कष्ट करें। यह किसानों के दु:ख-दर्द का अहम मसला है। पिछले 20 सालों से प्रदेश के लोगों को बहकाया जा रहा था। आज जब किसानों को कुछ सुख की सांस मिली है तो उन्हें थोड़ा अहसास हो रहा है कि सरकार हमारे साथ है। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि आगरा कैनाल की सफाई के लिए क्वैश्चन उठाया जाता था लेकिन आज तक उस नहर की कभी पूर्ण रूप से सफाई नहीं करवाई गई। हम देखते हैं कि उसमें खुण्डियां, गन्दा पानी और घास उग गई है और उनकी बहुत बुरी हालत है उनकी सफाई की बहुत आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बारे में इस सदन में प्रस्ताव पारित कर इनकी सफाई के लिए कुछ पैसा निश्चित किया जाए जिससे किसानों को पूरा पानी मिल सके। इसके अलावा हरियाणा के किसानों को जो आगरा कैनाल के पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं उनको हरियाणा के आबियाना से तीन गुना ज्यादा आबियाना उत्तर प्रदेश सरकार को देना पड़ता है। यह पैसा उत्तर प्रदेश के खजाने की बजाय हरियाणा के खजाने में जाए। अब किसानों को अपनी शिकायत लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों के पास आगरा जाना पड़ता है मैं चाहता हूं कि वे अफसर पलवल या फरीदाबाद में बैठें और रिकार्ड वहां रखा जाए ताकि किसानों को आने-जाने में दिक्कत न हो। मैं एक बात की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा कि रजवाहों पर जो पुल बने हुए हैं वह उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाए हुए हैं आज तक किसी सरकार ने यह नहीं सोचा कि यह काफी पुराने हो चुके हैं और कभी टूटेंगी भी। मेरे क्षेत्र हसन पुर में एक घसेड़ा गांव है वहां पर रजवाहे पर जो पुल है उस पुल से ट्रैक्टर गुजर रहा था वह उसके अंदर चला गया और उस पर सवार तीन लोगों में से एक की मृत्यु हो गई। तो मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार रजवाहों के निर्माण का काम अपने हाथ में लिया है इसी प्रकार पुल निर्माण का कार्य भी अपने हाथ में लिया जाए। मैं रजवाहे पक्के करवाने के लिए भी अनुरोध करूंगा। इनसे किसानों का हित जुड़ा हुआ है हम किसान पर आधारित हैं किसान के पीछे चलने वाले हैं। इसके अलावा मैं एक बात

[श्री जगदीश नैयर]

11.00 बजे और कहना चाहूंगा कि हसनपुर, हथीन, होडल के रजवाहों की खुदाई के लिए सदन में प्रस्ताव पारित किया जाए। पिछली सरकार ने तो इस क्षेत्र का भट्ठा ही बैठा दिया। आज वहां के लोग किसी भी एम०एल०ए० पर विश्वास नहीं करते। आज मैं आपके माध्यम से एक अहम मुद्दा सदन में उठा रहा हूं। आज हसनपुर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भिवानी, हिसार, रोहतक जिलों की तरह फरीदाबाद जिले के लिए भी इस सदन में एक प्रस्ताव पास किया जाये क्योंकि फरीदाबाद जिला कभी भी सरकार बनाने में पीछे नहीं रहा है। एक और अहम मुद्दा मैं आपके माध्यम से इस सदन में लाना चाहता हूं और वह है आगरा नहर का नियंत्रण हरियाणा प्रदेश के हाथ में लेना। आज आगरा नहर के कुछ रजवाहों को हरियाणा सरकार ने अपने हाथ में लिया है। मैं इस सदन में आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि आगरा नहर के सभी रजबाहों को हरियाणा प्रदेश के कंट्रोल में लाने के लिए एक प्रस्ताव सदन में पेश किया जाये। क्योंकि सरकार को तो किसान के प्रति सहानुभूति है किसान के लिए तो हरेक सरकार एक जैसी है आज किसान के अंदर एक दुःख दर्द बसा हुआ है। अगर किसान के साथ अन्याय किया गया तो वे सरकार के प्रतिनिधियों को गांव में घुसने नहीं देंगे। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आज जो उन्होंने चालिस हजार रुपये नहरों की सफाई के लिए दिए थे उनसे आज फरीदाबाद की सभी नहरों में सफाई का काम चल रहा है। स्पीकर सर, एस०वाई०एल० का एक अहम मसला है यह मसला तब से चल रहा है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और इस सदन से प्रार्थना करूंगा कि एस०वाई०एल० के पानी के हिस्से में हमारे क्षेत्र फरीदाबाद का कहीं भी हिस्सा नहीं है मेरी आपसे प्रार्थना है कि फरीदाबाद को भी एस०वाई०एल० के पानी के हिस्से में शामिल किया जाये।

श्री अध्यक्ष : बैठिए। हर्ष कुमार जी आप बोलिए।

श्री हर्ष कुमार (हथीन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में अभी जो आगरा नहर का नियंत्रण उत्तर प्रदेश से हरियाणा में लेने का प्रश्न चल रहा है उसके बारे में कहना चाहता हूँ। उसका एक अहम कारण यह है कि 1961 से जब हमारा हरियाणा प्रदेश पंजाब प्रदेश के साथ था और पंजाब विधान सभा का हाऊस था तब से आगरा कैनाल का मसला उत्तर प्रदेश सरकार से हम अपने हाथ में लेने के लिए उठाते आ रहे हैं परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार कभी कोई बहाना बनाकर कभी कोई बहाना बनाकर इसको टालती आ रही थी। अब हमारी यह सरकार बनी है और चौधरी बंसी लाल की सरकार बनने के बाद यह शुभ घड़ी आई। हमारे नेता ने चुनावों में ही इस बात का वायदा किया था कि आगरा नहर का नियन्त्रण हम अपने हाथों में लेगें वह अब पूरा करने की दिशा में यह एक कदम है। आगरा नहर से 1,47,000 एकड़ जमीन हमारे फरीदाबाद और गुड़गावां जिलों की है जोकि इस आगरा नहर से सिंचित होती है और जिसमें 782 क्यूसिक पानी हमारे हिस्से को मिलता है और इन 11 चैनल्ज की लम्बाई 380 किलोमीटर बनती है। लेकिन पिछले 30 सालों से इस चैनल की खुदाई नहीं हुई है इस वजह से जो हमारा 782 क्यूसिक पानी का हिस्सा था वह मुश्किल से 300 क्यूसिक ही मिल पा रहा था और टेल तक पूरा पानी नहीं पहुंच पा रहा था। आज हमारी सरकार ने चालिस लाख रुपये मन्जूर करके आगरा कैनाल के कुछ चैनल्ज की मरम्मत अपने हाथ में ली है। उनसे फरीदाबाद व गुड़गांव जो मेवात का इलाका है, वहां पर पानी खारा है, ये चैनल्ज इस एरिया को कवर करते हैं। इस प्रकार से इस सरकार द्वारा आगरा कैनाल के चैनल्ज की मरम्मत अपने हाथ में लेने से मेवात के गांवों में आगरा कैनाल चैनल्ज की जो टेलज वहां आज पानी पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की तरफ से तथा उन किसानों की तरफ से जो इस आगरा कैनाल से सिंचाई करते हैं, उनकी तरफ से इस सदन में आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय जी का

धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो वायदे चुनावों से पहले किए थे, उनको बड़ी नेकनीयती से पूरा किया है तथा जो किसानों की दुर्दशा थी उसमें सुधार हुआ है। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। क्योंकि आज तक हमारे क्षेत्र की सिंचाई के लिए किसी भी मुख्य मंत्री ने ध्यान नहीं दिया था। मैं इस साहसिक कदम के लिए एक बार फिर आभार प्रकट करता हूँ, चाहे इस कार्य को करने में किसी पालिसी को बदलना पड़ा हो या किसी दखलंदाजी की वजह से हुआ हो। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में दो ब्रैन्ज अजीना और गोची से गुजरती हैं तथा हमारे इलाकों का वाटर लेवल 50-60 फुट नीचे तक पहुंच गया था। मुख्य मंत्री जी के आने से खाद्र का पानी निकाले जाने के बाद वहां पर जो बंध लगाए गए, उससे हमारे यहां 30 हज़ार एकड़ भूमि की सिंचाई हुई जो कभी न नहर से होती थी और न ही ट्यूबवैल्ज से, क्योंकि उस इलाके में खारा पानी है। इस स्कीम से वहां का वाटर लेवल 20-25 फुट तक बढ़ा। इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ और उत्तर प्रदेश में जहां पर आज लोकप्रिय सरकार नहीं है, फिर भी उन अधिकारियों ने जिन्होंने इस कार्य को करने में हमारा सहयोग किया और यह साहसिक कदम उठाकर के आगरा कैनाल के चैनल्ज की मरम्मत हमारी सरकार को सौंपी उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।

श्री सतपाल सांगवान (दादरी) : अध्यक्ष महोदय, आगरा कैनाल के संबंध में मुख्य समस्या वहां के किसानों की है। मथुरा और आगरा में उनके एक्सीयन और एस०ई० बैठते हैं और वहां पर किसानों की सबसे ज्यादा समस्या यह होती है कि जो भी रैवन्यू का केस होता है उसके लिए यू०पी० में जाना पड़ता है। मैं तो यह चाहता हूँ कि आगरा कैनाल का टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो भी है, वह अभी यू०पी० के पास है। वह हमारे पास होना चाहिए। इसमें ओखला से जो 4 कि०मी० का एरिया है, जहां से अलग-अलग डिस्ट्रिब्यूशन होती है, वहां का प्रबंध यू०पी० के पास है। जैसे कि भाई हर्ष कुमार जी ने कहा इनके एरिया में वहां पर 11 चैनल्ज हैं और उनमें से 9 चैनल्ज की सफाई बहुत बढ़िया हुई है। पहली बार हरियाणा में इतनी बढ़िया सफाई हुई है। इस बारे में पहले बहुत किल्लत थी और ठेकेदारों ने कभी अच्छा काम नहीं किया था। हमें इस बात का गर्व है और इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ तथा बधाई देता हूँ कि वे टेल तक पानी दे पाए हैं क्योंकि आज तक हमने हरियाणा में टेल तक पानी नहीं देखा है। (थंपिंग) दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह कैनाल हरियाणा के कंट्रोल में आए। मैं तो मुख्य मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी ही यू०पी० में कोई सरकार बन जाए तो इस केस को जरूर टेकअप करें। आज वहां आबियाना हमें इक्ट्ठा करना पड़ता है। फरीदाबाद के डी०सी० को वहां आबियाना इकट्ठा करना पड़ता है। वहां के फारमर्ज को एक और सबसे ज्यादा प्रोब्लम है जिसके बारे में हर्ष कुमार जी ने भी बताया है कि वहां के फारमर्ज से हरियाणा प्रदेश के दूसरे फारमर्ज से अढ़ाई गुणा ज्यादा आबियाना लिया जा रहा है जोकि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिए और वहां के फारमर्ज से भी वही अबियाना लिया जाना चाहिए जो आबियाना हरियाणा प्रदेश के दूसरे फारमर्ज से लिया जा रहा है। (धन्यवाद)।

श्री सोमवीर सिंह (लोहारू) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आगरा कैनाल जो कि पलवल और होडल के एरिया को पानी देती है उसके मेनली 11 चैनल्ज हैं जिनके बारे में मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य हर्ष कुमार जी ने बताया था। उन चैनल्ज की 380 किलोमीटर की लम्बाई है। उनकी सबसे ज्यादा जो समस्या है जो इन एरियाज के जमींदारों के सामने आती हैं वे 3-4 समस्याएं हैं। पहली समस्या तो यह है कि आगरा कैनाल का कंट्रोल यू०पी० गवर्नमैंट के पास है। दूसरी समस्या यह है कि वक्त पर समय पर पानी नहीं आता है। जो पानी पहले आता था वह बहुत ही कम आता था। तीसरी समस्या यह है कि उन एरियाज के किसानों से आबियाना बाकी हरियाणा प्रदेश के दूसरे किसानों से अढ़ाई

[श्री सोमबीर सिंह]

गुणा ज्यादा लिया जाता है इसलिए उन एरियाज के किसानों से भी दूसरे किसानों के बराबर ही आबियाना लिया जाना चाहिए। उस कैनाल के बारे में पानी की चोरी का या कोई दूसरा केस हो जाता है तो वहां के किसानों को मथुरा या आगरा की कोर्ट्स में जाना पड़ता है और उनको वहां की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए हरियाणा प्रदेश की वर्तमान सरकार ने यू०पी० गवर्नमैंट को जहां पर इस समय गवर्नर शासन है, से बातचीत की और जून, 1996 के अन्दर मुख्य मंत्री जी की तरफ से यू०पी० सरकार के पास एक पत्र गया। उसके बाद वहां पर औफिसर्ज लैवल पर यह बात हुई है कि जो हरियाणा प्रदेश के अन्दर चैनल्ज जाते हैं उनकी सफाई करने का काम हरियाणा सरकार को दे दिया जाए, उनकी सफाई का काम हरियाणा सरकार कर सकती है। उनकी सफाई के काम पर हरियाणा प्रदेश सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा। श्री हर्ष कुमार और जगदीश जी ने बोलते हुए बताया था कि पिछले करीब 20 साल से उस कैनाल की टेल पर पानी नहीं आया था। अब लोगों को उस कैनाल की टेल पर पूरा पानी मिल रहा है। हरियाणा सरकार ने उन चैनल्ज की मैंटीनैंस के लिए करीब 40 लाख रुपए मंजूर किए हैं। यू०पी० सरकार ने 9 चैनल्ज की सफाई करने के काम की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार को दी है। उन एरियाज के किसान जो काफी सालों से पानी के बारे में तकलीफ उठा रहे थे अब उनको काफी राहत मिलेगी। हम चाहते हैं कि जो बाकी की समस्याएं हैं उनको इस सदन की मार्फत उनकी सरकार के साथ उठाया जाए ताकि उन एरियाज के किसानों को जो तकलीफ हैं उनका कोई हल निकाला जा सके।

श्री खुरशीद अहमद (नूंह) : डिप्टी स्पीकर साहब, आज सदन के सामने हमारे माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव पेश किया है। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को बहुत दिन पहले पेश करने की जरूरत थी। इसमें थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है यह अच्छी बात है। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है उसका समाधान भी होना चाहिए। मेरे साथी जगदीश जी, सांगवान जी और हर्ष कुमार जी और सोमबीर जी ने जो अपने ख्यालात पेश किए हैं मैं उनसे सहमत हूं।

इस रैज्योल्यूशन की जो कापी है उसमें लिखा है -

"This house recommends to the State Government to take up with the Uttar Pradesh Government the matter regarding taking over the administrative control of the Agra Canal, passing through the Haryana Territory...."

तो इसकी सख्त जरूरत है, ऐडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे हाथ में आना चाहिए। इसका जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में मैं ज्यादा टाईम लेना चाहूंगा और बहुत जरूरी है। इसमें लिखा है-

".. and also to increase the share of water of Haryana State."

यमुना में से और पानी ले लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है और खासकर गुड़गांव और फरीदाबाद जिले के लिए यह पानी लेना बहुत जरूरी है हमारे साथ वहां जो हमेशा होता रहा है वह इस वक्त यानि इस सीजन में भी हो रहा है। रबी की फसल के लिए दिल्ली से इतना पानी तकसीम होता था और उनको हमने जमुना में दिल्ली से पहले मुनक से लेकर पानीपत के पास यमुना में डालते हैं और उसके बदले 600 क्यूसिक्स वहां डालते हैं। 300 क्यूसिक्स इन्टाईटलमैंट दिल्ली से आगे गुड़गांव कैनाल के लिए बनता है लेकिन इस रबी सीजन में जो हुआ है बहुत से दिनों तक एक क्यूसिक्स भी पानी नहीं मिल पाया और उसके बाद जो रिकार्ड मैंने वहां से पता किया है कुछ दिनों तक तो बिलकुल ही नहीं मिला बाकी दिनों में 75 क्यूसिक्स से लेकर 175 क्यूसिक्स तक पानी चला है। अभी भी मालूम नहीं आज इस हफ्ते में क्या

पोजीशन है। यह एक बड़ी भारी टिक्सलस क्वैश्चन है और इसके बाद आगे यमुना से पानी लेने में जो दिक्कत हमें आ रही है उसमें हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें यह डिसाईड किया है। 29-2-96 को यह डिसाईड किया है, जिसमें तकरीबन हमारे राईटस को कम किया है यह केस दिल्ली सिवरेज बोर्ड वर्सिज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ए०आई०आर०, 1996 सुप्रीम कोर्ट 2992 है। इसमें फाईनल आर्डर करते वक्त उन्होंने बड़े सख्त लफ्ज हरियाणा के लिए इस्तेमाल किए हैं। और उनसे आईन्दा यमुना से पानी लेने के लिए जहां तक मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई अपील नहीं है, सिर्फ रिव्यू की बात रह जाती है। लेकिन रिव्यू भी सुप्रीम कोर्ट में मानी जाये या न मानी जाये क्योंकि लैंग्वेज जो है उसमें उसने बड़े जोर से लिखा है कि -

> "That drinking is the most beneficial use of water and this need is so paramount that it cannot be made sub-servient to any other use of water, like irrigation."

तो हमें इरीगेशन के लिए पानी चाहिए तो हमेशा यह तलवार हमारे ऊपर खड़ी रहेगी। इस केस को जो हमारे आफिसर्ज फेस कर रहे थे वे भी सुप्रीम कोर्ट की कन्टैम्पट आफ कोर्ट से बाल-बाल बचे हैं क्योंकि जो पहले डिसिजन आया था उसमें विवाद रह गया था जिस कारण हमारे अधिकारी पानी नहीं दे पाये थे जिस कारण सारी स्थिति बिगड़ गई थी। इस बारे में मैं पैरा 9 पढ़ कर सुनाता हूं।

> "Despite the aforesaid being the position, we are refraining from using our contempt jurisdiction in as much as the learned Advocate General has assured that Haryana would see that Delhi gets as much of water which it is presently receiving through Jamuna, if so directed by us,. It is because of this statement that Shri Jaitley submitted that the Water Supply Undertaking is not keen to pursue the contempt proceedings. Commodore Sinha too has taken the same stand. It is this gesture alongwith the statement made by Learned Advocate General, which has let us to close this proceeding, despite the highly objectionable conduct of the concerned persons."

यानी वह डाप कर रहे हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है वह हाईली ओब्जैक्शन हमारे आफिसर्ज पर है। यानि हमारे आफिसर्ज का कैन्डैक्ट हाईली ओब्जैक्शनेबल बताया है। हमारे आफिसर्ज पर और इस मामले में जो उन्होंने आखिरी राईडर दिया है, वह अपने आर्डर में जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, वह इस प्रकार है-

> " We, therefore, close the proceeding by requiring Haryana to make available the aforesaid quantity of water to Delhi throughout the year. Let it be made clear that any violation of this direction would be viewed seriously and the guilty person would be dealt with appropriately. This order of ours would bind not only the parties to this proceeding, but also the Upper Jamuna River Board."

इससे आप अन्दाजा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है उससे हमारी ऑफिसर्ज की क्या पोजीशन रह जाती है। स्पीकर साहब, सरकार से मेरी प्रार्थना है इस फैसले पर रिव्यू फाईल किया जाए ताकि हमारे ऑफिसर्ज के सिर पर जो बोझ है वह कुछ कम हो सके। यू०पी० से दिल्ली को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। दिल्ली की प्यास इतनी ज्यादा है कि वह बुझने का नाम नहीं ले रही है। प्यासे

[श्री खुरशीद अहमद]

को पानी पिलाना चाहिए यह ह्यूमन बात है लेकिन कितनी प्यास है, दिल्ली को कितना पानी चाहिए, यह भी तय होना चाहिए। अगर हम अपना पानी दिल्ली को देते रहेंगे तो हमारे अपने लोगों के लिए पानी की कमी होगी इसमें कोई शक नहीं है। पानी की और उम्मीद हमें आगे ही नहीं है कि हमें ओखला बांध से पानी मिल जाएगा। एक और समस्या मेवात ऐरिया को पानी देने की भी है। उनको पानी पीने के लिए भी चाहिए और आबपाशी के लिए भी पानी की जरूरत उनको है। मेवात में पानी की समस्या के लिए प्रधान मन्त्री जी से नूह में बात हुई। उन्होंने जो बात कही और आश्वासन दिया उसके लिए सरकार का शुक्रिया। डिप्टी स्पीकर साहब, इसी के साथ गवर्नर एड्रैस में लिखा है-

> "A new scheme for construction of Mewat Canal costing Rs. 207 crore has been conceived after the Prime Minister's visit to benifit the Mewat region. It will soon be posed to the Government of India and the Planning Commission for approval and Central assistance."

तो इसके बारे में हमारे लोगों की अप्रिहैंसशन रही है कि ओखला ब्रान्च से नीचे जा कर इसको शुरु किया जा रहा है। यह स्कीम पहले ही 1979-80 से चली आ रही है इसका परपज़ पहले कुछ और था लेकिन बाद में गुड़गांव कैनाल वाटर स्कीम काकरोई से शुरु कर रही हैं ताकि हरियाणा के बाकी सिस्टम से यमुना के अलावा भी पानी मिल सके। दिल्ली को कितना दिया जाए। मूनक से दिल्ली को पानी दिया जा रहा है। इस प्रकार से जो इन्वैस्टमैंट किया जाएगा वह वेस्ट होगा और हमें पानी नहीं मिल पाएगा इसलिए मेरी सरकार से यह दरख्वास्त है कि मेवात कैनाल की जो स्कीम है उससे फारूख नगर, पटौदी और गुड़गांव तहसील का ऐरिया है, का कहा गया है इसमें तावडू तहसील का ऐरिया और सोहना तहसील का एरिया कवर होना चाहिए। अगर यह स्कीम उधर से जाती है तो इससे तीनों तहसील कवर हो जाती हैं और इसके साथ ही दिल्ली को पीने का पानी तो मिल रहा है लेकिन जो दिल्ली का यूज़ड पानी है इस्तेमाल किया हुआ सिवरेज का पानी ओखला में मिल जाएगा। आगे के ऐरिया में पीने को पानी का इस्तेमाल करने के लिए कोई बांध ही नहीं (विघ्न) अगर अभी इन चीजों को सोचें और मैसिव इन्वैस्टमैंट करें तभी हमें कुछ पानी मिल पाएगा अन्यथा हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साउथ हरियाणा में पानी का विवाद छिड़ा हुआ है। पिछली बार ऐस्टिमेटस कमेटी के चेयरमैन बेरी साहब ने यह मुद्दा तफसील से उठाया था कि 18 लाख एकड़ फुट पानी था और एस०वाई०एल० तो साउथ हरियाणा के लिए है उसमें अम्बाला तक का ऐरिया कवर होना चाहिए लेकिन वह इसमें नही हुआ है। अगर उससे पानी मिल जाता है तो वह पीने के लिए भी इस्तेमाल होगा। मेवात के खेतों के लिए भी पानी चाहिए और पीने का पानी। और जो नीचे का पानी है वह नमकीन है। इसके लिए जरूरी है कि जो मेवात कैनाल की पुरानी स्कीम है उसको उसी तरह से लेकर आगे चलाया जाए ताकि जिनके बारे में मैंने जिकर किया है उनको भी पानी मिले। हमारे ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है उसको रिव्यू करें। अगर यह नहीं होगा तो ओखला से आगे हम पानी नहीं दे पाएंगे। वहां पर मेरे ख्याल से कोई प्रौब्लम वाली बात नहीं है, वहां पर थोड़ी सी प्रैक्टीकल डिफिकल्टी है जो कि दूर हो सकती है। जिन जगहों की मैंने पहले भी बात कही है वहां से यह कैनाल निकले ताकि वहां के लोगों को पीने का पानी मिल सके। गुड़गांव कैनाल में जो पानी है यह हमारे लिए बहुत जरूरी है इस बारे में इरिगेशन डिपार्टमैंट ध्यान दे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिव्यू करवाएं। अगर कोई गुंजाइश निकले तो साउथ हरियाणा, फरीदाबाद और गुड़गांव जिले को पानी दिलाने के बारे में पूरी कोशिश की जाए। धन्यवाद।

श्री रामजी लाल (सढौरा अनुसूचित जाति) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो चर्चा चल रही है, आपने मुझे इस बारे में बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज यहां पर आगरा कैनाल का प्रश्न जारी है। मेरे आदरणीय खुर्शीद अहमद जी ने बताया की यमुना नहर डिस्ट्रिक्ट यमुना नगर से होकर गुजरती है लेकिन वहां पर इसका किसी को कोई फायदा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके इलाके से हैं हमारी खेती का जरिया एच०एस०एम०आई०टी०सी० है लेकिन इनके ट्यूबवैल खराब पड़े रहते हैं, किसी की मोटर जल जाती है तो किसी का कुछ खराब हो जाता है और वे खराब ही पड़े रहते हैं। अब वहां पर सारे कनैक्शन ही काट दिये गए हैं। हमारे यहां ओला वृष्टि हुई थी और मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम राहत देंगे। मैं इनका आभारी हूं कि इन्होंने कुछ मुआवजा दिलवाया। लेकिन यह मुआवजा काट कर दिया जा रहा है। मैं इनसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह पैसा नहीं कटना चाहिए। हमारे पास इरीगेशन का एम०आई०टी०सी० के अलावा कोई और चारा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि क्या हमें भी यमुना नहर से कोई नहर दी जाएगी ताकि हमारा इस एम०आई०टी०सी० से पीछा छूटे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे इस बारे में कदम उठाएं और हमारे ऐरिया में भी एक नहर दें ताकि हमें भी खेती करने के लिए यह सुविधा मिले। धन्यवाद।

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। आगरा कैनाल का जो इशु है या जो कैनाल है यह ब्रिटिश टाईम की है। उस समय जब इसको बनाया गया था तब ऐसी दिक्कत नहीं थी क्योंकि उस समय न तो उस समय हरियाणा था लेकिन पार्टीशन के बाद इस कैनाल को लेकर मुख्य समस्या यही आ रही है कि हमारे यहां के लोगों को पानी नहीं मिलता। दिल्ली से लेकर आगरा तक जितने भी फार्मर्ज हैं उनको इरीगेशन के लिए या पीने के पानी के लिए यह नहर बनाई गयी थी। पार्टीशन के बाद इस कैनाल का कंट्रोल यू०पी० गवर्नमैंट को दे दिया गया जिसके बाद से ही दिक्कत आनी शुरू हुई। इस कैनाल का कमांड ऐरिया तकरीबन डेढ़ लाख एकड़ है जो खास तौर से आगरा कैनाल के अंडर आता है लेकिन इसमें से केवल चालीस हजार एकड़ एरिये की ही सिंचाई हो पाती है साथ ही पानी जरूरत के समय पर आता भी नहीं है। जब पानी की उतनी जरूरत नहीं होती तब इस कैनाल में पानी आता है। जब तक आगरा कैनाल का कंट्रोल हमारी सरकार के हाथ में नहीं आएगा या फिर इसका ज्वाईंट कंट्रोल नहीं होगा तब तक हमें दिक्कतें आती रहेंगी। (इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि वर्तमान सरकार ने 6 रजवाहों का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। आप वहां इनकी सफाई कर सकते हैं लेकिन किसानों की तो मुख्यतः समस्या यही रही है कि जब उनको अपनी फसलों के लिए पानी की जरूरत होती है तब उनको पानी मिलता ही नहीं है। कई बार देखा गया है कि वहां के जितने भी इलाके हैं जैसे हथीन, बल्लभगढ़ या पलवल आदि तो वहां के एरिया के किसान हमेशा पानी मिलने से वंचित रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार को इस मामले में यू०पी० गवर्नमैंट के साथ या सैंट्रल गवर्नमैंट के साथ बातचीत करके इस कैनाल का पूरा कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि वहां के किसानों को इस कैनाल से समय पर पानी मिल सके। अध्यक्ष महोदय, केवल पानी न मिलने की बात यहां पर ही नहीं है बल्कि एस०वाई०एल० के अलावा हमारे यहां पर जो दूसरे पानी देने के सिस्टम हैं उनमें भी हमारे दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव हो रहा है और हमारे दक्षिणी हरियाणा को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि आप कम से कम अपने हाउस को तो कंट्रोल कर लें। जो महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी या गुड़गांव के हिस्से का पानी है वह भी उनको नहीं मिलता। इसलिए जब तक सरकार इस कैनाल का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। बजट में भी कहा गया है कि सरकार

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

मेवात कैनाल बनाने वाली है लेकिन ये उस कैनाल के लिए पानी कहां से लाएंगे ? इन्होंने यह भी कहा है कि इसको बनाने के लिए सैंट्रल गवर्नमैंट से पैसा लेकर आए हैं। लेकिन जब आपके पास पानी नहीं होगा तो आप क्या करेंगे ? हमारे पास आज तो ऐग्जिसटिंग वाटर है तो जब अभी वहां के रजबाहों में पानी नहीं आ रहा है तो फिर आप दूसरे जो रजबाहें बनाएंगे उनमें पानी कहां से लाएंगे ? पहले हमारी सरकार ने भी खासतौर से महेन्द्रगढ़ एवं रेवाड़ी में रजबाहे बनाए थे लेकिन पानी न मिलने की वजह से वे सूखे पड़े हुये हैं और खराब हो रहे हैं इसलिए अगर आप और बना देंगे और उनमें पानी नहीं मिलेगा और वे सूखे ही पड़े रहेंगे तो फिर उनको मेनटेन करना भी मुश्किल हो जाएगा। आपने जिन छः रजबाहों का कंट्रोल भी अपने हाथ में लिया है तो इनके लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको गुड़गांव और फरीदाबाद के एरिये को खुशहाल बनाना है तो इस मामले में आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान गवर्नमैंट भी ऐसा करती है जब उनको पानी की जरूरत नहीं होती तो वे साइबी नदी में पानी छोड़ देते हैं जो कि तबाही मचाता है। पिछले दिनों भी अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि राजस्थान सरकार ने ऐसा ही किया था जिसके कारण धारूहेड़ा आदि के एरिये में बहुत नुकसान हुआ था। वहां पर मसानी बैराज में शटर नहीं लगे थे इसलिए वहां नुकसान हुआ। जब तक मेन कैनाल का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। यह बात ठीक है कि आपने छह रजबाहे अपने कंट्रोल में लिए हैं लेकिन जब तक आपका ज्वाइंट कंट्रोल न हो या फिर सारा कंट्रोल आपके हाथ में न हो तब तक हरियाणा प्रदेश के किसान खुशहाल नहीं हो सकते हैं। धन्यवाद।

श्री रमेश कुमार (बड़ौदा, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा के हित में पानी के लिए चर्चा चल रही है और आगरा कैनाल के बारे में सभी साथियों ने अपने-अपने सुझाव रखे हैं। जो यह आगरा कैनाल है यह ओखला से निकलती है और इसका टोटल कंट्रोल उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में है। इसकी मेन्टीनेंस, रिपेयर का काम, मोगे आदि तथा और प्रबन्ध करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है। हरियाणा सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जब तक हरियाणा के हाथ में यह काम नहीं आएगा तब तक हरियाणा के किसानों का भला नहीं हो सकता है। इस कैनाल में 11 चैनल्ज और तीन डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं इनके बारे में भी कोई विचार नहीं किया जा रहा है इसके अलावा इस सरकार ने नारा दिया था कि हम एस०वाई०एल० को पूरा करेंगे और गंगा का पानी लेकर आएंगे और दादूपुर नलवी नहर को भी पूरा करवाएंगे। आज हरियाणा प्रदेश के लोग इस सरकार की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं कि इस सरकार ने जो वायदा किया था उसे पूरा करेगी। इन्होंने एस०वाई०एल० का मुद्दा लेकर विधान सभा में प्रवेश किया था लेकिन आज न तो हरियाणा में एस०वाई०एल० का पानी आया है और न ही दादूपुर नलवी नहर को पूरा किया गया है। गंगा के पानी के बारे में इन्होंने कहा था कि ऋषिकेश से लेकर करनाल तक नहर के काम को पूरा किया जाएगा लेकिन आज तक इसको पूरा न किया गया। यह हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ सरासर अन्याय है। दक्षिणी हरियाणा के किसानों को अपनी फसल को पानी देने के लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि आज पानी जमीन के अंदर नहीं है और जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक किसान अपनी फसल के उत्पादन को नहीं बढ़ा सकता है। मैं खासकर सोनीपत जिले की ओर से आपसे यह अनुरोध करता हूं कि सोनीपत जिला भी एक ऐसा एरिया है जहां पानी खारा है और वहां नहरों में पानी अच्छी तरह से नहीं आता है। जब तक हरियाणा सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से आगरा कैनाल का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं लेगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। पिछले दिनों कुछ दूसरी स्टेटों को हरियाणा का पानी दिया गया था लेकिन सरकार ने उनकी ओर कोई तवज्जो नहीं दी थी। हरियाणा सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। रजबाहों

में जो सफाई का काम चला हुआ था वह बंद है। रजवाहों की कोई सफाई नहीं हो रही है। मेरे हल्के में बुटाना डिस्ट्रीब्यूटरी है वहां कोई सफाई नहीं है। वहां ट्यूबवैल भी नहीं चलते क्योंकि बिजली ही नहीं आती है। इसलिए किसानों के लिए जो बुटाना डिस्ट्रीब्यूटरी है उस नहर की सफाई की जाये ताकि किसानों को पानी मिल सके और आगरा कैनाल का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए। जय हिन्द, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : जसविन्द्र सिंह जी बोलिए।

श्री जसविन्द्र सिंह संधु (पेहवा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय साथियों ने आगरा कैनाल का कंट्रोल हरियाणा सरकार के हाथ में लेने के बारे में जो रेजोल्यूशन दिया है यह एक अच्छा प्रयास है जैसा कि पहले बताया गया है कि 6 चैनल्ज का कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया है। माननीय साथी श्री हर्ष कुमार जी ने बताया कि आगरा नहर का कंट्रोल हरियाणा सरकार के हाथ में आ जाने के बाद उस नहर की सफाई हुई और उसके बाद उनके क्षेत्र का वाटर टेबल ऊंचा हो गया है। स्पीकर सर, आज जो पानी की चिन्ता है वह सभी हरियाणा वासियों की चिन्ता है और यह जब से हरियाणा प्रदेश अलहदा हुआ है यह समस्या चल रही है क्योंकि पंजाब से हमें एस०वाई०एल० का पानी मिलना था परन्तु उस पानी को लाने में हम कामयाब नहीं हुए हैं। पिछली सरकार ने तो हरियाणा प्रदेश का पानी का हिस्सा घटाकर दूसरे प्रदेशों को दे दिया और इसके बारे में चौधरी बंसीलाल भी विरोध करते रहे थे। आज वैसी बात नहीं होनी चाहिए। जैसा की माननीय साथी श्री रमेश खटक जी ने बताया कि चौधरी बंसी लाल जी ने तो चुनाव प्रचार किया था कि अगर हमारी सरकार आ गई तो एस०वाई०एल० का पानी लेकर आएंगे। परन्तु इस सरकार ने कभी भी इस बारे विपक्षी दलों के साथ विचारविमर्श नहीं किया। माननीय साथी कैप्टन अजय सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रताव के जरिये नारनौल और रेवाड़ी में बिजली के बिल बढ़ने का कारण पानी की कमी की बजह से बताया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पहले पंजाब और हरियाणा इकट्ठे थे और कुछ साल ही हुये हैं जब ये अलग हुए हैं। आज पंजाब के मुख्य मंत्री ने वहां की जनता के लिए पानी और बिजली बिल्कुल फ्री कर दिये हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे भी बिजली और पानी को बिल्कुल फ्री कर दें। स्पीकर सर, आगरा कैनाल का कंट्रोल हमारे स्टेट के पास आ गया है तो एक अच्छा प्रयास है। इससे हमें फायदा भी होगा। आगरा कैनाल का कंट्रोल हमारी स्टेट के हाथों में आने से फरीदाबाद और गुड़गावां के यानि दक्षिणी हरियाणा को ज्यादा फायदा होगा। यदि मुख्य मंत्री जी के मन में दया आ जाए तो इसका इंडायरेक्ट फायदा अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों को भी हो सकता है। जब चौधरी बंसी लाल जी पहले मुख्य मंत्री बने थे तो हमारे अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिसकी सिंचाई नरवाना बाँच से होती थी, उससे एम०आई०टी०सी० के ट्यूबवैलों द्वारा पानी आगे ले गए थे। उस समय वजह कुछ और थी लेकिन उस कारण आज हमारे इलाकों का बाटर टेबल 100 फीट से ज्यादा नीचे चला गया है उस पानी को निकालने के लिए हमें मोटर को 90-100 फीट नीचे लगाना पड़ता है। पहले 5 हार्स पावर की मोटर से काम चल सकता था परन्तु आज 20-25 हार्स पावर की मोटर लगानी पड़ रही है। मेरा आपके जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरजोर अनुरोध है कि हमारे वाटर लेवल को उपर लाने के लिए प्रयास अवश्य किये जायें वरना हमारा क्षेत्र राजस्थान बनने वाला है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक बात और कहूंगा कि आगरा कैनाल का कंट्रोल जल्दी से जल्दी अपने हाथ में लें। इसके साथ ही यमुना कैनाल का समझौता है और एस०वाई०एल० का मसला है उसके बारे में भी सीरियस होकर प्रयास करें। इसके साथ ही मैं अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : चौधरी बीरेन्द्र सिंह, आप बोलिये।

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

श्री बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां) : स्पीकर महोदय, यह जो नॉन आफिसियल रेजोल्यूशन हमारे कुछ माननीय विधायक श्री जगदीश जी ने दिया है कि आगरा कैनाल जो बेसिकली एरिया है, वह यू०पी० को ही सिंचित करती है और कुछ हिस्सा हरियाणा राज्य का भी उस नहर से सिंचित होता है। उसके कंट्रोल के बारे में ये प्रस्ताव लेकर आए हैं। यहां पर जो हमारे माननीय साथी हैं ये उसी इलाके से संबंध रखते हैं और हर चुनाव में वहां के लोगों से वायदा किया जाता है। खासतौर से 4-5 विधान सभा क्षेत्रों की मैं बात कर सकता हूं जैसे कि बल्लभगढ़, हसनपुर, हथीन, पलवल और कुछ इलाका फिरोजपुर झिरका और नूंह का जोकि इस नहर से सिंचित होता है और इसके साथ ही आगरा कैनाल के अप-स्ट्रीम वहां से गुड़गांव कैनाल भी निकलती है। जब भी चुनाव होते हैं तो हरियाणा में दो ही मुख्य मुद्दे हर राजनैतिक दल अपने-अपने तरीके से किसानों के पास, देहात के लोगों के पास, हरियाणा की जनता के पास लेकर के जाता है कि हमें वोट दो। वे कहते हैं कि अब की बार अगर हमें सत्ता में लेकर के आओगे तो हम आगरा कैनाल का कंट्रोल हासिल करेंगे तथा जहां तक हरियाणा का क्षेत्र है वहां पर यू०पी० सरकार का कोई दखल नहीं होगा और हम वह नहर चलाएंगे हमारा उस पर पूरा कब्जा होगा। इसके अतिरिक्त, दूसरा मुद्दा हर बार हर राजनीतिक दल यह लेकर के आता है कि हमें सत्ता सौंप दो तो हम आपको एस०वाई०एल० नहर का पानी लाकर के देंगे। आज स्थिति यह है कि यह बात सुनते-सुनते अब हरियाणा के लोगों ने यह विश्वास कर लिया है कि यह बात सिर्फ चुनावी वायदे तक ही सीमित है तथा इन बातों पर किसी मुख्यमंत्री ने किसी सरकार ने कोई सीरियसनैस से कभी इस पर अमल करने की कोशिश नहीं की। पिछले 26 साल से एस०वाई०एल० का मुद्दा भी इसी प्रकार लटका पड़ा रहा। लेकिन क्लेम यह किया जाता है कि 85 प्रतिशत काम हो गया। बंसी लाल जी आएंगे तो कहेंगे कि ज्यादातर काम उन्होंने करवाया है, चौ० भजन लाल जी कहेंगे कि उनके राज में नहीं मेरे राज में यह कार्य हुआ है तथा चौटाला साहब को तो समय नहीं मिला। 6 महीने तक ये मुख्य मंत्री रहे तथा इस दौरान 3 बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन चौ० देवी लाल जी को समय मिला था, उन्होंने तो 4 साल हरियाणा पर राज किया है। उन्होंने वायदा किया था कि हम एस०वाई०एल० कैनाल लेकर के आएंगे। लेकिन मेरा अपना आगरा कैनाल के बारे में नजरिया है। मैं यह मानता हूँ कि अगर हम कोशिश करते रहे कि आगरा कैनाल का हरियाणा के क्षेत्र से गुजरने तक का कंट्रोल हम यू०पी० सरकार से ले सकेंगे तो मुझे इस बात की संभावना नजर नहीं आती है। हर्ष जी ने कहा कि कुछ चैनल्ज का कंट्रोल शायद हरियाणा सरकार के पास आने के बारे में कोई बात हुई है। यह कंट्रोल मिला है या नहीं मिला है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पूछना है। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या एक यही समाधान है कि यू०पी० सरकार से उसका कंट्रोल हासिल करें या कोई दूसरा समाधान भी है जिससे कि यू०पी० सरकार का दखल ही खत्म हो जाए। मेरा अपना यह मानना है कि पीछे कितनी मीटिंगें हुई। 1973 से लगातार कैनाल के कंट्रोल के बारे में बार-बार मीटिंगें हुई हैं। सचिव लैवल पर भी, मंत्री लैवल पर भी और दोनों सरकारों की आपस में भी मीटिंग हुई हैं लेकिन कोई निष्कर्ष या परिणाम नहीं निकाल सके हैं और इसकी वजह यही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस ने इस देश को 6-7 प्रधानमंत्री दिए हों और जो अपने आप में एक विशाल देश है। वह प्रदेश नहीं है। उसकी आबादी को अगर देखा जाए तो वह दुनिया का छठा देश है। दुनिया में ऐसे 5 देश हैं जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से ज्यादा है और फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। 16 करोड़ की आबादी का जो प्रांत हो उसे हरियाणा सरकार वन-टू-वन डील करे। केन्द्रीय सरकार को भी अगर तकलीफ हुई तो उसको यू०पी० की तरफ सहानुभूति रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि क्या हम इसका कोई दूसरा ऑप्शन तलाश कर सकते हैं। एक बार पहले एक ऐसी स्कीम बनी थी। जहां से यह कैनाल

टेकऑफ करती है और टेकऑफ करने की जगह से लेकर जहां पर हरियाणा प्रान्त की सीमा समाप्त होती है वहां तक इसके साथ-साथ एक पैरलल चैनल हम तैयार करेंगे। उस समय के एस्टिमेट के मुताबिक उस पर लगभग 6 करोड़ रुपये खर्च होने थे। जब हम उसके साथ-साथ एक पैरलल चैनल तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे तो उस पर किसी के कंट्रोल की जरूरत नहीं होगी उस पर हमारा ही कंट्रोल होगा जहां से यह नहर टेक आफ करेगी। औखला से जहां से यह नहर टेक आफ करेगी और हरियाणा प्रदेश की सीमा तक जितनी डिस्ट्रीबयूटरीज हैं जितनी माइनर हैं, उनको पूरा पानी मिल जाएगा। आगरा कैनाल 780 क्यूसिक की हो सकती है। जैसे हमारे माननीय मंत्री श्री कर्ण सिंह दलाल ने बताया था कि 780 क्यूसिक्स पानी का हरियाणा का हिस्सा है। मेरा अपना यह मानना है कि अगर हम इस तरह का प्रावधान कर सकें तो यू०पी० सरकार से हमारा कुछ लेना देना नहीं होगा। हम अपने किसानों को सही तौर पर फायदा पहुंचा सकेंगे। क्यों जगदीश नायर जी मेरी बात ठीक है।

श्री जगदीश नैयर : जी हां। आपकी बात ठीक है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : हमारे माननीय सदस्य श्री खुरशीद अहमद जी ने भी एक बात की तरफ इशारा किया कि 1994 में राजस्थान, दिल्ली, यू०पी० हरियाणा प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सरकारों का जो जल समझौता हुआ उसमें भी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने प्वायंट लूज किया। हम उस समय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। उस समय हमने यमुना अकोर्ड को नहीं माना था। उस समझौते को हमने गलत माना था। इस सदन के और भी बहुत से दूसरे सदस्य हैं जो उस समय भी सदस्य थे उन्होंने भी यमुना अकोर्ड को गलत माना था। मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। दिल्ली डेढ़ करोड़ की आबादी का शहर है। वह देश की राजधानी है। जो शहर अपना एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व रखता हो उसको हम प्यासा छोड़ दें तो यह बात भी ठीक नहीं है। मैं यह देख रहा था यह दलील सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट में भी दी गई है। मेरा मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि उस यमुना अकोर्ड की सार्थकता तभी हो सकती है जब उस अकोर्ड में अपर रीचीज पर किसाउ और रेणुका डैम्ज को बनाने के लिए प्राथमिकता दें। केन्द्रीय सरकार को हम इस बात के लिए सहमत कराएं कि किसाउ और रेणुका डैम को बनाया जाए क्योंकि जो यमुना रीबर है अगर उसको हम पैरनियल रीवर की संज्ञा देते हैं तो कई बार ताजेवाला हैड के नीचे वह नहर एक बरसाती नहर नजर आती है। यमुना रीवर तो गंगर रीवर की तरह बरसात के मौसम में भरकर चलती है और बाकी 8-9 महीने खाली रहती है उसकी वजह यह है कि उधर से इस्टर्न यमुना कैनाल और वैस्टर्न यमुना कैनाल अपना हिस्सा ले लेती हैं जिसके कारण ताजेवाला हैड के नीचे पानी नहीं जाता है। यमुना रीबर में पानी कम होने के कारण दिल्ली को पानी देने के लिए भाखड़ा नहर का पानी बुणक हैड वर्कस से यमुना रीवर में डाल कर दिया जा रहा है। मेरा अपना यह कहना है कि वैस्टर्न यमुना कैनाल सिस्टम से जो सिंचाई के लिए पानी मिलना है उसमें हमारे 14 जिलों का हिस्सा है, उस पानी से हमारे 14 जिले सिंचित हो जाते हैं लेकिन आज वे 14 जिले पानी के लिए तरस रहे हैं। एक तरफ हम एस०वाई०एल० कैनाल की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि आप एस०वाई०एल० नहर की बात तो एक तरफ रखिए, वह पता नहीं, कब पूरी तरह से मुकम्मल होगी, वह एक अलग स्थिति बनती है। लेकिन उससे पहले अगर हम अपनी प्राथमिकता देखते तो किसाउ डैम से यमुना के पानी को रैगूलेट किया जा सकता है जो 3 महीने फल्ड वाटर है जो बारिश का पानी है उसको अगर वहां से रैगूलेट किया जाये तो सारा डब्ल्यू०जे०सी० सिस्टम है उसके पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और जो आगरा कैनाल है, उस में पर्याप्त मात्रा में पानी जा सकता है। यह बात बिल्कुल सही है अगर आप गुड़गांव नहर और आगरा कैनाल का पानी देखें तो ऐसा लगता है जैसे गन्दे नाले का पानी है। वह पानी सिंचाई के लिए भी ठीक नहीं है और अगर वह पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है तो इससे भयानक स्थिति हो ही नहीं

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

सकती। जैसे काला तेल होता है, इस तरह से वह पानी है और उसमें दिल्ली का सारा गन्दा पानी बहा जाता है और पता नहीं एनवायरनमैंट के लोग कहां सोए हुए हैं। मेवात के अन्दर अगर 83 प्रतिशत जनता का हिमोगलोबिन 6 प्रतिशत से नीचे है, मेवात के अन्दर, अगर गरीबी है मेवात के अन्दर, अगर लोग पूरा भोजन प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस चीज को हम स्वास्थ्य के लिए अच्छा मानते हैं वह है पोर्टेबल वाटर, हम अगर वही पानी आंख से देखने से पता लगता है कि इससे गन्दा पानी हो ही नहीं सकता उसको पीने की स्थिति में क्या हाल होता होगा। स्वास्थ्य की स्थिति में क्या हाल होता होगा। उस में मैं मानता हूँ कि अगर सबसे बड़ी जो महामारी वहां पर फैली थी, डेंगू के नाम से उसमें यह भी एक कारण होगा। मैं उसको डेंगू की बीमारी नहीं मानता क्योंकि डेंगू तो अमीर आदमियों के घरों में होता है, मच्छर वहीं होते हैं जहां पर अमीर लोगों के पास एयर कन्डीशन्ड और कूलर हैं, वहीं मच्छर आकर बैठ जाता है, वे गन्दे पानी पर आकर नहीं बैठते। बीमारी की जगह तो है वह पोल्यूटिड वाटर है जो औखला हैड वर्कस से गुड़गांव कैनाल का और आगरा कैनाल में जाता है। मेरे ऐसा कहने से अभिप्राय यह है कि डब्ल्यू०जे०सी० सिस्टम को स्ट्रैन्थन करने के लिए और इस गन्दे पानी से बचने के लिए एक ही समाधान है कि हम किशाउ डैम की प्राथमिकता को समझें। किशाउ डैम आज से 65 साल पहले कन्सीव किया गया था। इस डैम की बड़ी इम्पोर्टेन्स थी जो आज भाखड़ा डैम की है। भाखड़ा डैम जिसमें सतलुज, में रावी से पानी मिलेगा। अगर ये न होती तो भाखड़ा डैम भी नहीं होता तो फिर इन नहरों की संज्ञा भी बदल दी जाती और कह सकते हैं कि जैसे यमुना रीवर है, वह ताजेवाला हैडवर्कस से नीचे नजर नहीं आती यही स्थिति यहां भी बनती क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने इस बात को कंसीव किया कि गंगा का पानी हरियाणा को मिले जब आप इलैक्शन लड़ रहे थे। आपने अपने भाषणों में 1100 क्यूसिक नहर की बात कही थी। वह हो सकता है, फिलहाल वह अपने में एक स्वप्न नजर आता है, हो सकता है कि वह एक ड्रीम हो लेकिन पोसीबल है, उसकी पोसिबिलिटी को एक्सपोलयट किया जाना चाहिए। कई बार ऐसा प्रतीत होता है। यह बड़ी अजीब स्थिति है। कई बार जो इन्जीनियर्ज हैं, ब्यूरोक्रेटस हैं, इकोनोमिस्ट्स हैं, वह यह कहकर उस प्रोजैक्ट को नकार देते हैं कि इसकी कोस्ट बढ़ेगी। कोस्ट के हिसाब से इससे कोई फायदा नहीं है। मुख्यमंत्री जी आपको याद होगा, 1968 से पहले जब आप पहले मुख्य मंत्री बने थे उस वक्त आपने घग्गर, भाखड़ा, टांगरी इन तीनों नदियों पर बैराज बनाने का एक प्रोजैक्ट तैयार करवाया था और इस बैराज बनने की स्थिति में यह कहा गया था कि यह बैराज बन कर तैयार हो जाएगा तो हरियाणा में सारे साल में से 3 नहरों में दो महीने के लिये पानी मिल सकता है और कॉस्ट ऑफ बैनिफिट रेशो के आधार पर उन बैराज को शैल्व कर दिया गया है ठण्डे बस्ते में रख दिया गया है। मैं आज भी मानता हूं कि हम कब तक हरियाणा की जनता को राजनैतिक तौर पर एस०वाई०एल० के नाम पर गलतफहमी में डालते रहेंगे या गंगा के नाम पर या यमुना के नाम पर उन्हें सपने दिखाते रहेंगे। स्पीकर साहब, किसाऊ डैम का मैंने जिक्र किया if with all seriousness it is taken up, then there is a possibility that Yamuna river can be called as perrenial river, otherwise it is no more a perrenial river.

लेकिन मैं कहता हूं कि यह बैराज भी आप बनाएं। हरियाणा सरकार के मन में एक बात कॉस्ट ऑफ बैनिफिट रेशो की हो सकती है इससे इसको कुछ भी लेना-देना नहीं है। I want to find out different sources of water than SYL and Yamuna. जो एक सीरियस इशू बचा हुआ है जिसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। अगर यह बैराज बना दिया जाए तो इसमें दो चीजें हैं। एक चीज

तो यह होगी कि जो सरकार ने शिवालिक डिवैल्पमैंट बोर्ड बनाया हुआ है उसके बारे में मैंने न्यूज पढ़ी है कि 5 साल में 31 करोड़ का प्रावधान किया गया है, यह इस बोर्ड के साथ एक प्रकार का मजाक है। चाहे मेवात बोर्ड हो या शिवालिक डिवैल्पमैंट बोर्ड हो उसके लिए ज्यादा पैसे का प्रावधान होना चाहिए। कालका से लेकर पौंटा साहब तक जितने फुट हिल्ज़ हैं उनमें सोयल इरोजन होता है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं 14 दिन के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना था तो उस वक्त मुझे इसे देखने का मौका मिला था उस वक्त मैंने देखा कि शिवालिक फुट हिल्ज़ में एक हजार वाटर मैनेजमैंट शैडज बनाने के लिए प्रावधान किया गया था आज आप जरा गहराई से इस बात को देखिए कि इस बात को 14-15 साल हो गये हैं। एक हजार प्वांयट्स आईडेंटीफाई किये गये थे और उनको बनाने के लिए तीन महकमें लगे हुए थे। फोरेस्ट वाले कह रहे थे कि यह हमारी रीचिज़ में है इन्हें हम बनाएंगे, नहर वाले महकमें के लोग कह रहे थे कि हम बनाएंगे और पंचायत राज महकमें वाले कहते थे कि हमारे सिस्टम में यह आते हैं इनको हम बना सकते हैं लेकिन कहीं पर कोई को-आर्डिनेशन नज़र नहीं आया। एक हजार में से केवल 26 बना पाए हैं। जब तक यह सभी शैडज नहीं बनेंगे तब तक सोयल इरोज़न को हम रोक नहीं सकेंगे। स्पीकर साहब, हरियाणा के अन्दर चाहे मेवात का ऐरिया हो, या फिर कालका, नारायणगढ़ का इलाका हो, साढौरा या कोई भी दूसरा इलाका हो सारे में वाटर शैडज़ तैयार कर दिए जाएं और फलोरिकल्चर और होर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। जिस प्रकार कश्मीर में हालात खराब होने के बाद हिमाचल प्रदेश ने नाशपाती और सेब की मार्किट हथिया ली है हम भी उसी प्रकार से फलोरिकल्चर और होर्टिकल्चर की मार्कीट कैप्चर कर सकते हैं। यहां की हालात और अर्थ व्यवस्था की ओर किसी का ध्यान नहीं है इस बात को गहराई से नहीं देखा गया है जैसे कि गवर्नर महोदय के एड्रैस में भी इसका जिक्र आया है और एक सवाल के जवाब में मन्त्री महोदय ने भी बताया है कि 1238 या 1307 करोड़ रुपये का राजस्व आ चुका है। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस में बताना चाहूंगा कि सोलह सौ कुछ करोड़ का यह लक्ष्य था जो रियलाईज़ किया जा चुका है वह तो उन्होंने बता दिया था उसके बाद फरवरी और मार्च का उसमें इन्क्लूड होना है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया कि इनकी टैक्सिज़ की रियलाइजेशन 13 सौ करोड़ से बढ़कर 16 सौ करोड़ हो गई है। (विघ्न) मैं तो यह कहता हूं कि आपकी रियलाजेशन 2 हजार करोड़ रुपये भी हो सकती है। इस बारे में मैंने कई बार मुख्य मंत्री जी से कहा लेकिन इस दशा में कुछ प्रयास नहीं किया गया। आपकी सरकार ने जहां प्रोहिबिशन को लागू किया, उसी के साथ टैक्सिज़ का भार भी चार सौ या पांच सौ करोड़ रुपये का इस प्रदेश पर पड़ा। इस वजह से बिजली की दरों को बढ़ाना पड़ा और बसों के भाड़ो को बढ़ाना पड़ा। इसके अलावा दूसरे कुछ नए टैक्सिज़ लगाए। मेरा अपना मानना है और अगर आप चाहें तो इस बारे में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट ले सकते हैं कि हरियाणा में कमर्शियल टैक्सिज़ की क्लैक्शन जो ऐक्चुल में होनी चाहिए उसकी 30 प्रतिशत की होती है। उस 30 प्रतिशत की भी हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी उन लोगों की है जो मैनेजमैंट में हिस्सेदार हैं और उन लोगों की जो बिजनैस चलाते हैं। 50 प्रतिशत टैक्स का टोटल इवेजन है। मेरा यह मानना नहीं है कि हमारा व्यापारी पर कोई एतवार नहीं है। लेकिन आज एक प्रथा बन गई है कि अगर मेरी 25 लाख की रिटर्न है तो मैं 15 लाख के टैक्सिज़ नहीं दिखाऊंगा। 10 लाख के दिखाऊंगा। 10 लाख की रिटर्न फाईल करूंगा और 5 लाख में शेयर करूंगा। अढ़ाई लाख रुपये खुद बचाऊंगा और अढ़ाई लाख रुपये बचाने वाले को दूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह प्रथा आज है। आधा पैसा रिटर्न में फाइल नहीं करूंगा। स्पीकर

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

साहब, कमर्शियल टैक्सिज़ के मिनिस्टर यहां पर नहीं बैठे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह सिस्टम क्या है। असैसी को तकलीफ हो तो वह हाई कोर्ट में जा सकता है। वहां पर भी उसकी तकलीफ न मिटे तो वह ट्रिब्यूनल में जा सकता है। ट्रिब्यूनल में बड़े-बड़े आई०ए०एस० आफिसर्ज बैठे हुए हैं वहां पर उनको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन जहां पर सरकार से धोखा हुआ है वहां सरकार किस अपील में जाती है, कब जाती है। इस टैक्सेशन के स्ट्रकचर में यह सबसे बड़ी एनोमली है। सरकार को अगर कोई 10 लाख का चूना लगा जाए उसका कुछ नहीं। जब मैं मंत्री था तो मैंने अफसरों से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, एसैसी को तो अख्तियार है, उसको तो प्रिवलेज है कि अगर उसको कोई तकलीफ है तो वह कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जाएगा। वे कहने लगे कि साहब ऐसी बात नहीं है, हम 10% केसिस की एट-रैंडम चैकिंग करते हैं। जहां हमें कुछ लगता है वहां हम उस केस को रि-ओपन कर देते हैं।

अगर सरकार की नीयत ठीक हो तो मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सरकार ने जो टैक्सिज़ बसों के भाड़े के रूप में और बिजली की दरों के बढ़ाकर लगाए हैं उसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपकी जो टैक्स कुलैक्शन 16 सौ करोड़ रुपये की है हम उससे ऊपर 2 हजार करोड़ रूपये तक या उससे भी ज्यादा जा सकते थे अगर आप उनके थोड़े से नट टाईट कर देते। अगर ऐसा होता तो किसी गरीब आदमी पर किसी नए टैक्स का भार नहीं पड़ सकता था। लेकिन इस दिशा में ये कुछ नहीं करते। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं बंसी लाल जी से कहना कहता हूं कि he enjoys a particular reputation as development oriented Chief Minister and that reputation is getting eroded. (विघ्न) स्पीकर साहब, अगर इनको पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो डिवैल्पमैंट कहां से होगी। पूरा पैसा लेने के लिए हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि हमने कई वलंडर्ज किए हैं। पैसे की कमी की वजह से हमने नाथपा झाखड़ी प्रोजैक्ट से अपना हिस्सा वापिस ले लिया, पैसे की कमी की वजह से थीन डैम से घबरा कर बाहर चले गए और पैसे की ही कमी की वजह से ही किसाऊ डैम के ऊपर कोई सीरीयसनैस नहीं है। यह सारी वजह है जिसकी वजह से हम पानी के लिए तरसते हैं। अब हम सोचते हैं कि चलो और कुछ नहीं तो गुड़गांवा कैनाल का कंट्रोल अपने हाथ में लेने से कुछ हमारा काम चल जाए और हमारे पानी में इजाफा हो जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब तक किशाऊ डैम नहीं बन जाता तब तक हम वहां पर कोई टैम्परेरी अरेंजमैंट कर सकते हैं। पता नहीं कि खुर्शीद जी मेरी इस बात को पंसद करेंगे या नहीं लेकिन मेरा अपना विचार है कि मेवात के इलाके में बहुत झील हैं और उनका सारा पानी उजीना डायवरशन ड्रेन के थ्रू निकल जाता है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यमुना में बारिश का पानी होता है तो उस पानी को अगर इंजीनियर्ज डायवर्ट करके उन्हीं ड्रेन से उन लेक्स में डाल दें अलग अलग जगहों पर तो उस पानी को वहां से मेवात के सारे किसान अपनी दो फसलें पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीकर सर, इस हरियाणा का एक तिहाई से ज्यादा, 35 परसैंट से ज्यादा हिस्सा जो कि रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों में पड़ता है ऐसा है जहां पर किसान को सही तौर पर एक ही फसल मिलती है। ये ऐसे जिलें हैं जहां लोगों को पानी न मिलने की वजह से एक ही फसल पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर सरकार वहां के किसानों को भी यह विश्वास दिलाए कि उनको भी पूरा पानी मिलेगा तो उन ऐरियाज के किसान भी दो फसलों की बजाए तीन फसलें पैदा कर सकते हैं। स्पीकर सर, मैं एक गांव का नाम तो नहीं लेता लेकिन यह गांव कुरुक्षेत्र जिले में हमारी बिरादरी का है। जब तीस साल पहले वहां पर गेहूं या जीरी पैदा नहीं होती थी तो वहां के जाट के रिश्ते दूसरे गांव के जाट नहीं लेते थे। (विघ्न) लेकिन जब ग्रीन रैवेल्यूशन आयी तो उस गांव में कोठी उभर आयीं और अब लोगों का कहना यह है कि हमारी उन से बात कराओ तो स्पीकर सर, आर्थिक

स्थिति आदमी का सारा कुछ बदल देती है। मैं यह कहता हूं कि आज अगर मेवात के इलाके में, सोनीपत के इलाके में और रोहतक के इलाकों में फर्क है तो इस फर्क का कारण यही है कि वहां एक फसल पैदा होती है। हम इस बात को नकार नहीं सकते। मेरा आपसे यह कहना है कि यमुना के पानी की और बरसात के पानी की आज जो यूटिलाइज करने की पद्धति है, उसका अगर हम सही इस्तेमाल करें तो सारे का सारा मेवात का इलाका ठीक हो सकता है। इस इलाके में मेन क्राप सरसों ही है और इसके अलावा वहां कोई दूसरी क्राप पैदा नहीं होती। साथ ही वहां पर नीचे का पानी खारा है और जो पहाड़ों से पानी आता है वह तबाही मचाता है। अगर वहां पर भी वाटर शेड का प्रावधान किया जाए तो उस इलाके का भी पूरा दोहन हो सकता है और वे हिल्ज हार्टीकल्चर के लिए दोहन की जा सकती हैं तथा वहां के लोगों की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि खेती ऐसा धंधा है जिसमें खेत के मजदूर की सारी उम्र की हिस्सेदारी है। किसान अपनी दो ढाई हजार की आमदनी से चार साढ़े चार हजार रुपये की आमदनी से खुश रहता है लेकिन जो दूसरे धंधे हैं जैसे व्यापार है, इंडस्ट्री है वहां पैसा मल्टीप्लाई होता है यानी चार से आठ, आठ से सोलह और सोलह से बत्तीस बनता है लेकिन किसान के साथ ऐसा नहीं होता है। आज जिसको हम उदारीकरण कहते हैं और जिसका पदार्पण पिछले पांच छः सालों में भारत के अन्दर हुआ है। आज प० जवाहर लाल नेहरू के सौशलिज्म का पता लगता है कि उस आदमी का उस समय क्या वीजन था और जिसकी वजह से पिछले 35-40 सालों में भारत के मध्यम वर्ग का ब्रोडगेज हुआ था। आज जब से उदारीकरण की नीति आई है तो हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी। आज अगर हम किसान को बिजली एवं पानी देने का प्रबन्ध नहीं करेंगे जो तो पहले मध्यम वर्ग ऊपर उठकर आया था, वह फिर हटकर पीछे चला जाएगा और उसकी आर्थिक दशा खराब हो जाएगी। अगर उसकी आर्थिक दशा खराब हो गयी तो जो किसानों का शोषण करने की स्थिति में होंगे, वह उसका शोषण कर सकते हैं। दिल्ली हमारे बीच में है और हरियाणा से दिल्ली साढ़े तीन तरफ से घिरा हुआ है दिल्ली भारत की राजधानी है और सन् 1985 से पहले दिल्ली को हम भारत की राजधानी कहते जरूर थे लेकिन जब कॉमर्शियल कैपिटल की बात आती थी तो बम्बई को कौमर्शियल कैपिटल माना जाता था लेकिन 1985 के बाद कामर्शियल ऐक्टीविटीज भी दिल्ली की तरफ डायवर्ट हुई हैं। मुख्य मंत्री जी मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अगले 10-15 सालों में दिल्ली के चारों तरफ सौ-सौ किलोमीटर तक बोने खाने की जमीने नहीं बचेंगी। इस बैल्ट के अंदर टोटली इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा हरियाणा के लोग उठाते हैं, या दिल्ली के लोग उठाते हैं या बाहर के व्यापारी या उद्योगपति उठाते हैं या मल्टी नेशनल्ज फर्म उठाती हैं। इस प्रश्न का फैसला जो सरकार या पार्टी पावर में है उसने लेना है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से 39 हजार के करीब उद्योग घरों में लगे हुए थे उनको वहां से शिफ्ट करने की हिदायत हो चुकी है उनमें से कुछ को बेशक दिल्ली सरकार कहीं कौम्पलैक्स बनाकर जमीन भी मुहैया करा दें तो भी हजारों इंडस्ट्री हरियाणा में आकर लगेंगी। अब दिल्ली सरकार के बारे में टिप्पणी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है लेकिन मैं एक बात आपको अवश्य कहना चाहता हूं कि जो 39 हजार के करीब इंडस्ट्रीज दिल्ली में लगी हुई हैं। Most of the industries deal with plastic and most of the people who deal with these industries are there from Haryana. खुद उन फैक्ट्री वालो के मुंह से सुनी हुई बात मैं आपको बता रहा हूं वे कहते हैं कि अगर हम बिजली की चोरी न करें तो इस इंडस्ट्री में हमें कुछ न मिले। यानी बिजली के बारे में चर्चा के लिए तो अध्यक्ष महोदय आप या मुख्य मंत्री जी अलाऊ करेंगे तो बिजली के बारे में मैं रहस्योद्घाटन करूंगा। बिजली के बारे में बहुत सी बाते हैं (विघ्न) दिल्ली के हरियाणा से घिरा होने की वजह से हमें अपनी सम्पूर्ण उद्योग नीति को नये सिरे से बनाना पड़ेगा। मेरा आपसे कहना है कि अगर इस औद्योगिक नीति को हम सोचकर बनायेंगे तो उसके परिणाम पांच साल के बाद हमें मिलने शुरू

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

हो जायेंगे। उसकी एक वजह है। अध्यक्ष महोदय, इण्डस्ट्री तो आयेंगी ही उनका तो कोई चारा नहीं है। बहादुरगढ़ में पिछले 35 सालों से रोहतक-दिल्ली रोड़ पर कोई उद्योगपति जमीन लेने को तैयार नहीं था और आज दिल्ली से लेकर रोहतक तक सड़क दोनों तरफ एक किला दस लाख रुपये में या 15-20 लाख रुपये से कम नहीं मिल रहा है यह बात मैं इस लिए कह रहा हूं कि ऐसी हालत आज से एक डेढ़ साल पहले नहीं थी। और ऐसी स्थिति रही तो वहां से किसानों की सारी जमीन बिक जायेगी। क्योंकि जब किसी किसान की एक एकड़ जमीन 15-20 लाख रुपये में बिकेगी तो लालच तो होगा ही और जो उद्योगपति 5 एकड़ जमीन लेकर उद्योग स्थापित करेगा तो उस उद्योग में 200 आदमियों को रोजगार मिलेगा और उन 200 आदमियों में से 70-80 आदमी टैक्नोक्रेट होते हैं जोकि स्कील्ड वर्कर होते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हमारे बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए। हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको आज दसवीं, प्लस टू और बी०ए०, एम०ए० की सर्टीफिकेट लेने के बाद नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। आज आई०टी०आई० में भी इस लिए धक्के खा रहे हैं कि हमारी कंजरवेटिव अप्रोच होती है कि ट्रेक्टर मकैनिक का कोर्स कर लिया। आज इनकी जरूरत नहीं है। आज हमारे प्रदेश में नये कोर्स इन्ट्रोडयूस करने की जरूरत है। एम०बी०ए० की बजाय आज बिजनैस संबंधी कम्पनी सक्रेटरी कोर्स करवाने की जरूरत है या कोई ऐसा कोर्स हो जिसमें एकाउंटस संबंधी, इलैक्ट्रोनिक्स, कम्प्यूटर संबंधी कोर्स हों। आज हमारे यहां ऐसे बहुत कम कोर्स हैं अगर कहीं हैं तो नाम मात्र के हैं। अगर कहीं पर इन कोर्सिज की ट्रेनिंग दी जाती है और इन संस्थाओं से हमारे बच्चे ट्रेनिंग करके आते हैं उनको इन फैक्ट्रियों में तरजीह नहीं दी जा रही है। मेरा कहना यह है कि पांच एकड़ जमीन जिस भी किसान की गई और उसमें 200 आदमियों को रोजगार मिला और उन 200 आदमियों में से उस फैक्ट्री में सिर्फ गेट खोलने वाला और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो एक्स सर्विसमैन उस इलाके के होते हैं उनको रोजगार दिया जाता है। लेकिन वहां जो स्कील्ड् वर्कर हैं जो दफ्तर चलाते हैं या मशीनरी चलाते हैं वे हमारे बेटे या भाई नहीं होते क्योंकि किसी भी सरकार ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। आज जरूरत इस बात की है कि दिल्ली के चारों तरफ 100 किलोमीटर के अंदर जो स्कूल हैं, कालेज हैं, हाई स्कूल हैं, प्लस टू या पोलीटैक्निक कालेज हैं इनमें जिन कोर्सिज की ट्रेनिंग दी जाती है उनको अनुबंध किया जाए जैसे एम०बी०ए० या आई०टी०आई० वगैरह में को अनुबंध किया जाता है। वहां पर जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं उनको पहले एक फैक्ट्री वाला ओफर देता है कि हम 15 हजार रुपये देंगे तो दस दिन बाद दूसरी फैक्ट्री वाला आ जाता है कि हम 18 हजार रुपया महीना देंगे। ऐसे ही अनुबंध हमारे यहां पर भी होने चाहिएं। पांचवे पे कमीशन ने यह बात कही है कि क्लास फोर पोस्टस को खत्म करके कौन्ट्रेक्ट बेसिस पर काम करवाया जाये। इससे तो हमारे बच्चों का और गरीब आदमी का ज्यादा शोषण होगा। मैं मुख्य मंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा कि जब ये सिविल एवियेशन और सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तब एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स में एक प्रथा चली थी कि वहां जो सिक्यूरिटी स्टाफ है उनको भी कंट्रैक्टच्यूल बेसिस पर नौकरी दी जाये (विघ्न)।

श्री बंसी लाल : यह विभाग मेरे पास नहीं था।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, गांवों में से एक ठेकेदार 50-100 बच्चों को पकड़ता है और उनकी ड्रेस सिलवा देता है और इन फैक्ट्रियों में उनको 1200, 1400, 1600, 1800 या 2000 रुपये मासिक के हिसाब से लगवा देता है और फैक्ट्री मालिक से उनकी चार हजार रुपये मासिक के हिसाब से तनख्वाह लेता है। इस तरह से जो बाकी पैसा बचता है वह ठेकेदार अपने पास रख लेता है। यह शोषण है। अगर हमारे बच्चे इस शोषण का शिकार हो गए तो हमारी हालत भी उन राज्यों जैसी हो जाएगी जहां

पर भूख है और शोषण आज भी है। जहां आज भी फयूडल स्टाइल का कल्चर है। इस लिए अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं एक नजरिए से इसलिए कहना चाहता हूं कि जो हरियाणा के अन्दर उद्योगों का विकास होगा (विघ्न) उसमें दो तीन इंस्टीटयूशन बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। एक फिक्की, एक चैंबर ऑफ कामर्स और एक सी०आई०आई०। ये तीनों जो उद्योग की आर्गेनाइजेशन हैं इनसे सम्पर्क स्थापित करके इनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि आने वाले 5, 7, 10, सालों में वे प्रोजैक्शन दें कि फलां ट्रेड में उनको इतने आदमी चाहेंगे, उस सैक्टर में इतने चाहेंगे और फलां सैक्टर में इतने चाहेंगे। ऐसी उनको ऑफर दी जानी चाहिये। अपने एक्सपर्ट भी बनाने के लिए उनको खुद ही इंसट्रक्टर भी भेजने चाहिएं और उन बच्चों को बाद में वे नौकरी दें। यह सब एक एग्रीमैंट के द्वारा होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को धक्के न खाने पड़ें तथा दौड़ न लगानी पड़े। हरियाणा में तो जैसे एक प्रथा चल गई है तथा यह सोच नौकरियों में होने लग गई है। इसलिए इससे भी आजादी मिल जाएगी। आज हरियाणा में यह हालत है कि एक एक गांव में सौ-दो सौ लड़के कुंवारे बैठे हैं, कोई लड़की वाला रिश्ते लेकर के नहीं आता है। आएगा भी कैसे, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। कौन बेकारों के साथ अपनी लड़की का रिश्ता जोड़ेगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यह जो इलाका है, गुरबत में है। अगर हम आगरा कैनाल को खुद चलाएं, मेरा मतलब यह है कि अगर हम अपनी कैनाल बनाकर चलाएं, गुड़गांव कैनाल को बढ़ाएं और मेवात कैनाल जिसके लिए 200 करोड़ रुपये का नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया गया है, उसको स्पीड-अप करें तो अच्छा रहेगा। बड़ा दुख होता है कि यह बात सदन के अंदर कई बार कही जा चुकी है। मैं बताना चाहता हूं कि गुड़गांव के अंदर 10-15 मंजिली बिल्डिंगों के लिए रोहतक के गावों को चीरती हुई नहर आ सकती है लेकिन मेवात के अंदर वह पानी आगे बढ़कर नहीं जा सकता क्योंकि पानी नहीं है और उनके लिए पानी की सुविधा नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस दृष्टि से कि किसानों की आमदनी बढ़े, एग्रीकल्चर सैक्टर में हमारी पूरी हिस्सेदारी हो, इसके लिए हमारे बच्चों के अंगूठे से ही मशीन का स्विच दबे तो कल्याण होगा। यह पूने या हैदराबाद में रहने वालों के हाथों से दबेगा तो इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए सरकार को औद्योगिक नीति को, कृषि नीति को व वाटर मैनेजमैंट की नीति को बदलने के लिए आज शिक्षा की नीति को बदलना पड़ेगा। शिक्षा के नए आयाम कायम करने पड़ेंगे ताकि हम अपने बच्चों को इस दिशा में बढ़ते हुए देख सकें और वे भी इसी तरह की हिस्सेदारी कर सकें। मेरे को कई लोग कहते हैं कि यह जात-पात की बात है। यह जात-पात की बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा में 22000-26000 कांस्टेबल हैं इनमें सारे हरियाणा में आप देखें कि कहीं पर भी चैन नहीं मिलेगा। अगर कहीं पर मिलेगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यह एक कल्चर डिवैल्प हो गई है। स्पीकर साहब, हमारे बच्चे तो सिर्फ कांस्टेबल या सिपाही बनें, वे बर्फ की चोटी पर खड़े रहें। इस प्रथा को बदलने के लिए और समाज के अंदर परिवर्तन लाने के लिए यह बात जरूरी है कि आगरा कैनाल को नियंत्रण लेने का जो मुद्दा अपने माननीय साथियों ने रखा है वह सराहनीय है। (विघ्न) मैं यह कहना चाहता हूं कि इस नहर पर कंट्रोल की बात को छोड़कर आप अपनी नहर बनाएं ताकि हरियाणा के किसान पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि उनको इंसाफ मिलेगा तथा उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। धन्यवाद।

श्री राम पाल माजरा (पाई) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की पानी की समस्या पानी के डिसप्यूट इन्टर स्टेटस हैं उसी में से आगरा कैनाल का कंट्रोल भी एक डिसप्यूट है। जहां यमुना जल समझौता एक डिसप्यूट है तो वहीं एस०वाई०एल० कैनाल का भी एक डिसप्यूट है। इन सभी डिसप्यूटस के बारे में हरियाणा प्रदेश की सरकार चिन्तित भी है। पहले की सरकारों के जिस प्रकार के दस्तावेज हमारे सामने आए हैं उनसे ऐसा लगता है कि वे सरकारें भी इन डिसप्यूटस के बारे में चिन्तित रही हैं। आगरा

[श्री राम पाल माजरा]

कैनाल 150 वर्ष पुरानी कैनाल है तब से ही इसका कंट्रोल यू०पी० सरकार के पास है। अनेकों प्रकार के सेक्रेटरीज की मीटिंग्ज हुई और मुख्यमंत्रियों की मीटिंग्ज हुई लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि इस बारे में कोई निर्णय नहीं हो सका कोई फैसला उस जगह पर नहीं आ सका। आगरा कैनाल के बारे में किसानों की बहुत सी समस्याएं हैं क्योंकि हरियाणा प्रदेश के किसानों को अनेकों प्रकार के मुकद्मों के लिए यू०पी० में जाना पड़ता है। उनके आगरा और मथुरा में जे०ई०, एक्सीयन और एस०डी०ओ० बैठते हैं इसलिए किसानों को वहां पर आने जाने में बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वहां पर उस एरिया के किसानों का कोई भाईचारा या रिश्तेदार नहीं रहता जिसके पास वे उनके पास रूक जाएं क्योंकि उनको वहां पर एक दो दिन के लिए रूकना भी पड़ता है। जहां तक उस नहर के पानी की मात्रा का सवाल है जिस चैनल में 150 क्यूसिक पानी छोड़ना चाहिए चूंकि मैनेजमैंट उनके हाथ में है जिसकी वजह से वे 20 या 25 क्यूसिक पानी छोड़कर कह देते हैं कि उन्होंने पूरा पानी छोड़ दिया। इसलिए उसका कंट्रोल हरियाणा प्रदेश की सरकारें अपने हाथ में लेने के लिए काफी प्रयास करती रही हैं। उस नहर का एडमिनिसट्रेटिव कंट्रोल हरियाणा सरकार के हाथ में लेने के बारे में उस एरिया के किसानों की एक आवाज है एक जरूरत है। आगरा कैनाल का पानी बढ़ गया। पहले आगरा कैनाल में जो पानी आता था वह इसलिए बढ़ गया क्योंकि फरीदाबाद और दिल्ली शहरों का सीवरेज का पानी उसमें आता है और कंग नहर का पानी भी उसमें मिल जाता है जिसका वजह से उसका पानी बढ़ गया है। पहले हमारा हिस्सा 20 प्रतिशत था। हमारी सरकार को चाहिए कि पानी बढ़ाने के बारे में हमारी सरकार अपनी तरफ से इस केस को यू०पी० सरकार के साथ एक समन्वय स्थापित करके केस प्लीड करे और अपने हिस्से को बढ़वाने के यत्न करे ताकि हरियाणा प्रदेश के किसानों की तरक्की हो सके और उनको पूरा पानी मिल सके। किसानों को उसका फायदा हो सके। जहां तक नहरों की डीसिल्टिंग का सवाल है। नहरों की डीसिल्टिंग के बारे में हमारे साथी हर्ष कुमार जी ने कहा और हमारे साथी जगदीश नायर जी ने भी खुशी मनाई कि उनकी डीसिल्टिंग हुई है। हमें भी इस बात की खुशी हुई है कि इनके चैनैल्ज की सफाई तो हो गई क्योंकि नहरों की डीसिल्टिंग के लिए 40 लाख रुपये मंजूर किए गए थे। उन्होंने इसका ब्यौरा भी दे दिया और कह दिया कि पानी टेल तक पहुंचना शुरू हो गया है। लेकिन मैं कहता हूं कि हरियाणा प्रदेश की हर नहर की टेल तक पानी पहुंचाने के लिए उनको डीसिल्टिंग की जरूरत है। नहरों की डीसिल्टिंग के बारे में अनेकों प्रकार के एस्टिमेट बनाए जाते हैं और ठेकेदार उन एस्टिमेटस के टैंडर ले लेते हैं जिसकी बिना पर नहरों की डीसिल्टिंग की जाती है। उनके फर्जी बिल बना दिए जाते हैं और पेमेंट ले ली जाती है। यह बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है कि हर ठेकेदार को एस०डी०ओ०, एक्सीयन, और जे०ई० यहां तक कि ऊपर तक दो तीन परसैंट कमीशन देना ही पड़ता है चाहे कोई कितना ही ईमानदार ठेकेदार क्यों न हो फिर भी उसको कमिशन तो देना ही पड़ेगा । अगर हरियाणा सरकार अपने प्रदेश में हर नहर की डीसिल्टिंग करवाना चाहती है तो सिंचाई विभाग के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पुनः ओवरहाल करना पड़ेगा और उनकी जो पुरानी आदत है मैं यह नहीं कहता कि उनकी यह आज की आदत है मैं कहता हूं कि यह उनकी पुरानी आदत है इसलिए इस विभाग का ओवरहाल करना चाहिए ताकि ठेकेदारों को उस से छुटकारा मिल सके। नहरों की सफाई हो सके और पानी टेल तक पंहुच सके। आज के लीडर ऑफ दि हाउस भी भीमगोड़ा से नहर लाने की बात कहा करते थे लेकिन आज भीमगोड़ से नहर लाने की बात का जिक्र नहीं हो रहा है। वह नहर बहुत जरूरी है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, और करनाल जिलों का वाटर लैवल बहुत नीचे चला गया है। दादूपुर नहर के बारे में हाउस के अंदर बार-बार जिक्र होता रहा है। दादूपुर नहर 1987 में मंजूर हुई थी और उसके लिए 180 एकड़ जमीन भी एक्वायर की जा चुकी

थी। दादूपुर नहर बनाने के लिए उस समय केवल 13 करोड़ रुपये खर्च होने थे अगर आज उस नहर को बनाना है तो उस पर आज 70 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मेरा सरकार से निवेदन है कि जहां पर आगरा कैनाल हरियाणा प्रदेश की लाइफ लाइन है तो वहां पर दादूपुर नहर कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और करनाल जिलों के लिए बहुत जरूरी है। मैं इस रैजोल्यूशन का समर्थन करता हूं और इतना ही कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश की सरकार को दिलेरी के साथ, मुख्य मंत्री जी पहले भी ध्यान देते रहे हैं और अपनी जनसभाओं में भी कहते रहते थे कि हरियाणा के साथ अन्याय हुआ है। पहली सरकार ने कुर्सी से चिपके रहने के लिए यह सौदा किया है। हमारा उस समझौते से पहले 70 प्रतिशत पानी जो बनता था, वह नहीं मिल रहा। अध्यक्ष महोदय हरियाणा प्रदेश का, इसी प्रकार से एस०वाई०एल० का प्रश्न है, हरियाणा प्रदेश की बहबूदी और किसानों की तरक्की से बंधा हुआ प्रश्न है, हरियाणा की यह एक लाइफ लाईन है और हम किसानों की आर्थिक उन्नति का ढिंढोरा पीटते हैं जबकि हर तरफ से किसान मारा जाता है। कभी उसको दबाई चढ़ जाती है, कभी आसमानी बिजली गिर जाती है, कभी किसान को कुएं में जाकर पट्टा चढ़ाना होता है तो वहीं पर ढेर हो जाता है। हमारे इलाके में 150 फुट पर जाकर वाटर लैवल है और किसान कुएं के अन्दर ही रह जाता है और किसान का नौजवान बेटा जब कुएं में पट्टा चढ़ाने के लिए जाता है तो बाप ऊपर खड़ा रहता है और इंतजार करता रहता है कि बेटा वापस आएगा लेकिन वह वापिस नहीं आता। मैं चौधरी बंसी लाल जी से कहूंगा कि हमारे इलाके में यह बहुत बड़ी समस्या है, आप इसकी तरफ ध्यान दें। जब आगुमन्टेशन कैनाल बनाई गई थी तो उस वक्त एम०आई०टी०सी० ने काफी टयूबवैल्ज आगुमन्टेशन कैनाल के लिए लगाए थे जिस कारण वाटर लैवल नीचे चला गया। वह पानी भिवानी चला गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि खेती करते हुए मरने वाले किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए क्योंकि जिसका नौजवान बेटा इस देश के लिए अनाज पैदा करते करते कुएं में ही रह जाता है। अध्यक्ष महोदय, गांवों में कई बार लाईन मेंन नहीं होता, इलैक्ट्रीशियन नहीं होता, कई बार किसान बिजली का तार लगने से मर जाता है क्योंकि उससे उसको करंट लग जाता है और वह वहीं पर ढेर हो जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार का प्रोविजन बनाएं कि किसान इन परिस्थितियों में मरे तो उसे जरूर मुआवजा दिया जाना चाहिए। मैं इस सरकार का इस तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बहुत से किसानों को पानी की समस्या इसलिए भी है कि हरियाणा प्रदेश में वाटर लैवल नीचे चला गया है और बहुत सी जगहों पर पानी खारा है। इस नहरी पानी की इसलिए भी आवश्यकता है कि ताकि वाटर लैवल ऊपर आ सके और खारे पानी के साथ इसको मिलाकर कुछ खेती की जा सके। धन्यवाद।

श्री करतार सिंह भडाना (संभालखा) : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे हरियाणा में जो नहर का कार्य मुख्यमंत्री जी ने किया है, कैनाल के पानी की जो हमको सहुलियत दी है उसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर हमारे किसान कई बार ट्रैक्टर से नहर से पानी ले लेते हैं यानि पानी उठा लिया जाता है तो उन पर केस बना दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अर्ज करता हूं कि उन पर केस न बनाएं जायें। दूसरे जहां तक अभी मेरे सीनियर सांसद और जो अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं उन्होंने कई सवाल किए क्योंकि यहां पर राजनीतिक बातें बहुत हो जाती हैं लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या है उसकी तरफ कोई भी ख्याल नहीं करता। पानी हम सबको देना चाहते हैं। यह जरूरी भी है। हरेक को पानी दिया जाना चाहिए, यह जरूरी है। लेकिन समस्या यह है कि हम अपना त्याग कोई भी नहीं कर पाते। अभी उन्होंने कहा आज तो सबसे बड़ी समस्या है वह गरीबी की है, उसकी हम सब बात करते हैं। हर आदमी चाहे वह बड़े से बड़ा कोई नेता हो, उसको ले लें वह गरीबों का साथ देता है क्योंकि हमारे देश, प्रदेश और शहर में गरीबों की संख्या ज्यादा है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि कम से कम हरियाणा में इस चीज को हटा दें क्योंकि अगर रईस और उंचे लोग ज्यादा होंगे तो यहां पर

[श्री करतार सिंह भडाना]

यह कहने वाले नेता कम मिलेंगे कि गरीबों का साथ दिया जाये। गरीबी की रेखा से सब ऊपर होना चाहते हैं लेकिन आज हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत है, वह कहते हैं कि रईस भी उसी पानी को पीता है और गरीब भी उसी पानी को पीकर जिन्दा रहता है। अगर रईस पानी के बिना जिन्दा रह सकता है तो क्या रईस को पानी नहीं दिया जाएगा ? यह कहा गया कि गुड़गांव की बड़ी-बड़ी बिल्डिंगज़ को पानी दिया जाता है। मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं कि पीने का पानी तो सभी को आवश्यक है ही और सबको बराबर पीने के पानी की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जो बहुत बड़े सीनियर नेता हैं वे कहते हैं कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए एक तरफ तो वे कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी तरफ बंटवारे की बात करते हैं। वे कांग्रेस का समर्थन करते हैं लेकिन इस प्रकार वे कांग्रेस के खिलाफ बात कर रहे हैं, अगर वे ऐसा चाहते हैं तो उन्हें बी०जे०पी० को स्पोर्ट करना चाहिए जो कि वे नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि ऐरियावाईज बात को छोड़कर और पार्टीवाईज़ बातों को भुलाकर सभी साथियों को सरकार द्वारा जो विकास और लोगों की भलाई के कार्य किए जा रहे हैं उनका समर्थन करना चाहिए। मैं अपने ओपोजीशन के भाईयों से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वे भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों की भावनाओं के खिलाफ कोई काम न करें। राजनीतिक बातों को छोड़कर राज्य के भले और विकास की बातों का समर्थन करें। इन शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष महोदय, का धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा (नारनौल) : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में इस विषय पर काफी चर्चा हुई है कि आगरा नहर का कंट्रोल हरियाणा सरकार अपने नियन्त्रण में ले ले। मुझे ऐसा लगता है कि सारा सदन ही इस पक्ष में है और यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होने जा रहा है। इसके लिए सारा सदन धन्यवाद का पात्र है। बोलते हुए श्री बीरेन्द्र सिंह जी बता रहे थे कि सोनीपत, पानीपत, और सारे मेवात एरिया का भी जिक्र किया है कि यह बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है यहां नहरें जरूरी हैं। परन्तु जिला महेन्द्रगढ़ जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है और एक फैसला है के लिए भी सभी साथी सोचें। स्पीकर साहब, आपके ज़रिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जिला महेनद्रगढ़ और रिवाड़ी की तरफ थोड़ा इन नहरों को मोड़ दिया जाये तो हमारे किसान का भी गुजारा हो सकता है इसलिए इधर ज्यादा ध्यान रखें। मुझे इस बात की खुशी है कि महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी जिले ऐसे जिले हैं जहां से भारत वर्ष में परसैंटेज के हिसाब से सब से ज्यादा लोग देश सेवा करते हैं। देश में सबसे ज्यादा परसैंटेज में यहां के लोग देश की पहरेदारी और देश की सेवा करते हैं। यहां के लोगों का सबसे ज्यादा परसैंटेज मिलेट्री में है लेकिन फिर भी यह इलाका पिछड़ा हुआ है। महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी की जल दर सबसे नीचे है। यहां पर 150 से 200 फुट नीचे से बिजली की मोटरों से पानी खींचा जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से मेरा आग्रह है कि दोहान और कृष्णावती दो नदियां राजस्थान से आती हैं। उनके अन्दर अगर सिर्फ एक एक किलोमीटर पर सिर्फ 5-5 फुट थोड़ी दीवार बांध के लिए खड़ी कर दी जाए जैसे कि राजस्थान के इलाके में है। एक एक किलो मीटर के फासले पर इस प्रकार से छोटे छोटे बांध बन जाएंगे और जब भी वर्षा आएगी तो इनमें पानी इक्ट्ठा हो जाएगा और जल स्तर ऊँचा हो जाएगा। इस प्रकार से इन नदियों पर 15-15 या 20-20 बांध बन जाएंगे जिनसे साथ लगते गांवों को फायदा हो सकता है। हमीदपुर बांध के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई थी और उसको भरने की योजना थी लेकिन ईश्वर की कृपा से वर्षा हुई और वह बांध पानी से भर गया। जिससे उसके नजदीक लगते 15-20 गांवों का फायदा हो गया है क्योंकि 20-20 फुट पानी ऊपर आ गया है। जिससे कुछ गांवों का फायदा भी हुआ है। आजकल महेन्द्रगढ़ में और रिवाड़ी में पानी का लैवल बहुत नीचे चला गया है। सरकार से मेरी

प्रार्थना है कि दोहान और कृष्णावती नदियों पर छोटे-छोटे बांध बनाएं जाएं उसके लिए सिर्फ 5-5 फुट की दीवार खड़ी करने की जरूरत है। वर्षा आने से इन बांधों में पानी इकट्ठा हो जाएगा और इसके नज़दीक लगते 300-400 गांवों का वाटर लैवल ऊंचा आने से दोनों नदियों के आसपास बसे गांवों को फायदा होगा।

इसी तरह से आगरा नहर को हरियाणा सरकार अपने प्रशासनिक नियन्त्रण में ले तो यह बहुत अच्छी बात है। ऐसा होने से यह पता रहेगा कि इसमें कितना पानी आता है कितना पानी आगे जाता है इस बारे में सारी रिपोर्ट ठीक मिलेगी। अगर यह नियन्त्रण किसी और के हाथ में होगा तो हमें ठीक रिपोर्ट नहीं मिल सकती है। मैं यह चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को सारे सदन को सर्वसम्मति से पास करना चाहिए।

इसी तरह से अभी पानी का हिस्सा बढ़ाने की बात आई थी इसके ऊपर भी यही बात लागू होती है। यह प्रस्ताव भी सारा सदन एक मत से पास करे। धन्यवाद।

श्री अशोक कुमार (थानेसर) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में आगरा कैनाल के कंट्रोल को अपने हाथ में लेने की बात चल रही है इसका जो प्रस्ताव आया है यह ठीक है। पानी न मिलने की वजह से किसानों को बहुत दिक्कत होती है। इस प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं। इसी के साथ मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जब आप हमारे यहां चुनावी जलसे में आए थे तो आपने वहां पर एक लम्बा चौड़ा भाषण दिया था कि आप कुरुक्षेत्र में दादुपुर नलवी नहर बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो आज आप मुख्यमंत्री हैं, आज राज आपका है तो आप इसे बनवाएं क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों को दादुपुर नलवी नहर की बहुत जरूरत है। यह बनाने से कुरुक्षेत्र के लोगों को पानी मिल जाएगा और वहां का वाटर लैवल भी ऊँचा हो जाएगा। जब आप पहले मुख्यमंत्री थे तो आपने नरवाना ब्रांच में बड़े-बड़े ट्यूबवैल्ज लगाकर इस प्रान्त में पानी देने का काम किया था। आज यहां पर औहदियां 70-70 फुट नीचे चली गई हैं और बरसातों में इनमें गैस बन जाने से लोगों की मौत होती है। मेरा यह कहना है कि यह जो एम०आई०टी०सी० के ट्यूबवैल्ज लगाए गए हैं इनको बंद किया जाए। बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा था कि पहले इस क्षेत्र में रिश्ते नहीं होते थे। मेरा ख्याल है अब फिर से रिश्ते होने बंद हो जाएंगे। दूसरे पिछली सरकार ने जो यमुना जल समझौता किया और हरियाणा के हिस्से का पानी कम कर दिया था तो उस प्रस्ताव के विरोध में भी यह सरकार एक और प्रस्ताव लाए और उसे पास करे। (विघ्न) स्पीकर सर, एस०वाई०एल० का जिक्र करना भी जरूरी है और यह हरियाणा प्रदेश के लोगों की जरूरत है। इसका बनना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुरुक्षेत्र के छोटे किसानों की 52 एकड़ जमीन एस०वाई०एल० की एक प्रयोगशाला बनाने के लिए ली थी। उस समय यह कहकर ली गई थी कि वहां पर एक प्रयोगशाला बनेगी। आज उस जमीन को लिए हुए लगभग बीस बाईस साल हो गये परन्तु वह जमीन उसी तरह से बेकार पड़ी हुई है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि रावगढ़ गांव के किसानों की वह जमीन वापस दिलायी जाए। सर, उस गांव में अरबाड़ी जाति के लोग हैं और उनके पास एक किल्ला ही जमीन थी लेकिन जब उनसे वह जमीन ले ली गई तो वह आज रिक्शा चलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि अगर इन्होंने वहां पर कोई प्रयोगशाला नहीं बनानी है तो वह जमीन किसानों को वापिस कर देनी चाहिए। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं डीप ट्यूबवैल्ज के बारे में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि या तो सरकार इनको बंद कर दे और अगर सरकार उनको बंद नहीं कर सकती तो जो नहरी पानी के रेट दूसरे लोगों से लिए जाते हैं उसी रेट पर कुरुक्षेत्र के लोगों को भी इनका पानी मिलना चाहिए। धन्यवाद।

श्री धीरपाल सिंह (बादली) : अध्यक्ष महोदय, आज तो हाऊस के सम्मानित साथियों ने यह प्रस्ताव हाउस के सामने रखा है मैं भी उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सर, यह समय की

[श्री धीरपाल सिंह]

मांग भी है जैसा चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि कई लोग आए और आकर उस इलाके के लोगों की भावनाओं के साथ शोषण करते हुए चले गए। फरीदाबाद और गुड़गांव के इलाकों में चुनावों से पहले आगरा कैनाल के मुद्दे को बार बार कैश किया गया। आज जो चौधरी बंसी लाल की वर्तमान में सरकार है इन्होंने भी दूसरे लोगों ने भी इस मुद्दे को कैश किया। हर्ष जी ने जो यह प्रस्ताव आज यहां पर रखा है तो यह केवल एक विधायक या इलाके की भावना नहीं बल्कि इससे सारा प्रदेश भी जुड़ा हुआ है क्योंकि पिछले काफी दिनों से आगरा कैनाल की वजह से वह इलाका पीड़ित रहा है और वहां के किसान को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए उत्तर प्रदेश में मथुरा या आगरा में ऐक्सियन या एस०ईज० के पास दो-दो सौ किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है। स्पीकर सर, आज भी यह संदेह है जैसा कि अखबारों में इरीगेशन सैक्रेटरी की तरफ से टिप्पणी हुई थी कि हमने यह बुलन्दबाग फैसला अपने पक्ष में फैसला करा लिया है। सर, अगर वाकई फैसला अपने पक्ष में हो गया है तो यह बहुत अच्छी बात है लेकिन संदेह यह है कि हम आज भी इस मामले में सक्षम नहीं हैं। न केवल कंट्रोल की बात बल्कि और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे उस इलाके के किसानों के साथ आबियाने को लेकर भी भेदभाव है। आज जो पूरे प्रदेश में आबियाना लिया जा रहा है ठीक उसके विपरीत वहां के किसानों से जो कि आगरा कैनाल से अपना इलाका सिंचित करते हैं, से काफी ज्यादा आबियाना लिया जाता है। आज जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं और उन्होंने इस बारे में जो आकड़े हाउस के सामने रखे थे, वह आंकड़े आज दर्शा रहे हैं कि कितना ज्यादा आबियाना वहां के किसानों को बर्दास्त करना पड़ता है। स्पीकर सर, केवल आबियाने में ही भेदभाव की बात नहीं है बल्कि बाराबंदी की बात है या पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो अगर एक-एक मुद्दे को देखा जाए तो आज वहां का किसान अपने आपको लाचार सा समझ रहा है लेकिन वहां पर किसानों की भावनाओं को समय समय पर कैश किया जाता रहा है। उस भावना की कीमती ओट में इस तरह की बात की जाती है। लेकिन इससे आगे कभी बात नहीं की गयी इसलिए आज जो यह प्रस्ताव हाउस में आया है उससे सारा हाउस सहमत है और उन इलाकों के किसानों के साथ, उनके अधिकारों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। जहां पर प्रदेश के हित, किसान के हित और गरीब के हित का मुद्दा आएगा वहां पर होगा वहां कोई पार्टियां नहीं होंगी। वहां सभी विधायक और सभी पार्टियां उस किसान के प्रति, गरीब के प्रति अपने आप को उतना ही सहयोगी मानती हैं जितना दूसरे लोग सहयोगी मानते हैं। आज फिर मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे को गम्भीरता से उठाया जाये। चाहे उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा हो, वहां सांसदों या विधायकों की संख्या ज्यादा हो लेकिन फिर भी हमारा प्रदेश कमजोर नहीं है, यहां का किसान कमजोर नहीं है, यहां की राजनीति में जो लोग हैं वे कमजोर नहीं हैं, और अपने आप को कमजोर नहीं मानते हैं फिर भी हमारे साथ अनहोनी बात की जा रही है, यह घाटे का काम किया जा रहा है हमारे यहां के लोगों व किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उनकी खेती को उजाड़ने का काम किया जा रहा है इसमें वर्तमान, भूतकाल और भविष्य सभी इसके लिए दोषी बनते हैं। इसी प्रकार इस बात से जुड़ती हुई वहां डीसिल्टिंग की बात है भाई हर्षकुमार जी ने इस बात की वकालत की है लोकतंत्र में सीमाएं भी हैं, मजबूरियां भी हैं। अभी हमें कंट्रोल मिला नहीं और उस कंट्रोल के लिए हम मुख्य मंत्री जी के साथ हैं। हमारी पार्टी इनके साथ है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि वहां डीसिल्टिंग कैसे हो गई। डीसिल्टिंग का अधिकार हमें नहीं है। हम चाहते हैं कि डीसिल्टिंग का अधिकार हमें मिलें, बाराबंदी का अधिकार हमें हो। पानी का कंट्रोल हमारे पास हो; नहर के रख-रखाव का कंट्रोल हमारे पास हो। जैसा अभी बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि इस पर कितनी लागत आती है। आज विषय लागत का नहीं है आज विषय नैतिकता का है आप पैसे के अभाव को कहीं और दूर

कर लीजिए। प्रदेश के लेवल पर या सरकार के लेवल पर इस समझौते में कोई रूकावट आती है या उत्तर प्रदेश की सरकार का पक्ष केन्द्र सरकार रखती है तो आपका यह दायित्व बनता है कि आप उसके साथ-साथ अलग कैनाल बनाकर उस इलाके को जो महरूम रह गया है, वंचित रह गया है उस इलाके को पानी दीजिए और यह उनका हक बनता है। इसी तरह से और इलाके भी हैं। मसानी बैराज पर चर्चा होती रही। वहां राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे सामने परेशानियां आई हैं। राजस्थान में साहिबी, दोहान और कृष्णावती यह जो नदियां बरसात के समय में वहां से आती थीं तो उनके साथ वहां की फर्टाइल मिट्टी भी आती थी और पानी भी फर्टाईल आता था और अब राजस्थान सरकार ने उन जगह पर जगह जगह छोटे छोटे बांध बनाये हुए हैं। आज चौधरी भजन लाल जी बैठे हुए नहीं हैं जब वे सत्ता में थे तब आपकी ओर हमारी पार्टी उन पर इस काम के लिए दबाव डालती थी लेकिन उन्होंने भी इसे अनदेखा किया। इस बारे में प्रयास मुख्य मंत्री जी के लैवल पर किया गया या नहीं किया गया यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन यदि प्रयास किया गया होता तो परिणाम अवश्य हमारे पक्ष में आते। अब अगर साहिबी में ज्यादा पानी आता है तो दिल्ली तक तबाही झेलनी पड़ती है अगर पानी की मात्रा कम रह जाती है तो पानी राजस्थान के इलाके में ही रह जाता है। आज मुख्य मंत्री जी के सामने यह भी प्रश्न है। छोटे-छोटे बांध बने हुए हैं और उनकी वजह से कुछ इलाका खुश्क रह गया है वहां पर भी पानी का स्तर नीचे जा रहा है। यह जो महेन्द्रगढ़, नारनौल और रेवाड़ी का इलाका है वहां पर भूमि के पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है। यह बहुत सोचने का विषय है। इसी तरह अगर पानी का स्तर नीचे चला गया तो पीने के पानी की वहां पर कठिनाई पैदा हो सकती है। और पता नहीं कि जमीन सिंचित हो पाएगी या नहीं। इस पानी के स्तर को बढ़ने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि हम राजस्थान सरकार से यह मामला उठायें कि जो उनके छोटे छोटे बांध बने हुए हैं पानी को रोकने के लिए और जो बरसाती पानी हमारे यहां आता है उसके बारे में कुछ कदम उठाए जाएं ताकि यह जो पानी का स्तर गिरता जा रहा है उस समस्या का हल निकाला जा सके। मैं मुख्य मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करूंगा कि वे इसमें व्यक्तिगत रूचि लें और पानी को यहां पर लाने का प्रयास करें ताकि किसानों को पानी की सुविधा प्रदान की जाये। इसके साथ ही साथ मैं मेवात क्षेत्र के बारे में बात कहना चाहूंगा। मेवात क्षेत्र में जो कोटला झील है उस झील में बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है और जब पानी की जरूरत होती है तो उसमें से किसानों को पानी दिया जाता है आज उस झील की हालत खस्ता हो गई है। वह कभी भी टूट सकती है और ओवरफ्लो होकर किसानों का भारी नुकसान कर सकती है। क्योंकि जो पानी बरसात में कोटला झील में इकट्ठा किया जाता है वह मौसम ठीक होने के बाद खालों में छोड़ दिया जाता है उसको इस हिसाब से बनाया जाये ताकि जरूरत पड़ने पर यह पानी किसानों को दिया जा सके। चाहे पम्प लगाकर ऐसा किया जाये।

श्री बंसीलाल : इस बार हमने इस पानी को इरीगेशन के लिए इस्तेमाल किया है।

श्री धीरपाल सिंह : अगर इरीगेशन के लिए इस्तेमाल किया है तो अच्छी बात है लेकिन यह पानी अभी भी छोड़ा गया है (विघ्न)।

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने साथी को बताना चाहूंगा कि उजीणा और गोच्छी में पहली दफा हरियाणा के इतिहास में हमारे मुख्य मंत्री जी के आदेशों से हथीन के पास आप स्वयं जाकर देख सकते हैं कि 14 बान्धों को दोनों नालों पर बनाया गया है। (विघ्न)

श्री धीर पाल सिंह : क्या इस पानी को रोककर बनाया गया है ? (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : पहली दफा इस नाले का पानी खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। इसके अलावा स्पीकर सर जो सबसे ज्यादा इस इलाके के लोगों को फायदा हुआ है वह यह है कि धरती के पानी का जल स्तर 5-6 फीट ऊपर आ गया है।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, अगर चौधरी बंसी लाल जी ने उजीणा डैम से सिंचाई के लिए पानी रोककर किसानों को यह सुविधा दी है तो यह एक अच्छी बात है। मैं एक दूसरे विषय के बारे में बताना चाहता हूं कि वह यह है कि कोटला झील में से एक नहर बनाकर पानी किसानों को दिया जाये क्योंकि आज डीजल मंहगा हो गया है बिजली की कमी है, बिजली न आने पर किसानों को बड़ी परेशानी होती है।

श्री बंसी लाल : आगे हम दोनों काम ले लेंगे, ड्रेन आउट करने का और आसपासी के पानी को लेने के लिए भी। अब की बार केवल बांध लगाये हैं आगे से दोनों को कर लेंगे।

श्री धीर पाल सिंह : हम चाहते हैं कि आगरा कैनाल का नियन्त्रण हरियाणा के पास हो। वाकई अगर मुख्य मंत्री जी वहां पर गये होंगे और चौधरी कर्ण सिंह जी बड़े योग्य हैं। हमने उनकी योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। लेकिन पानी के मामले में हम अवश्य कहेंगे कि आगरा कैनाल में जो पानी छोड़ा जा रहा है, वह पानी सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है लेकिन मजबूरी की वजह से शायद किसान उस पानी का प्रयोग करते होंगे। मरता हुआ किसान क्या नहीं करेगा। लेकिन अगर वही पानी कहीं पीने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा तो उस इलाके के लिए इससे बहुत दुखदायी बात कोई और नहीं हो सकती है। मेरा भी कई बार वास्ता हुआ है। मैं भी वहां पर गोवर्धन जी की परिक्रमा करने गया था। (विघ्न) मैं पानी की चर्चा पर ही बोल रहा हूं। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, परिक्रमा करना भी कोई बुरी बात नहीं है। अच्छी बात है, ये चैन पाएंगे। (हंसी)

श्री धीर पाल सिंह : मैं भगवान में विश्वास रखता हूं मालिक की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। (विघ्न) जैसा मालिक चाहता है वैसा ही होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उस पानी में जो गंद आ गई है, वह या तो नजफगढ़ नाले की है या सारी दिल्ली की है। आज तो मैं एक्जैरेसी के आधार पर नहीं कह सकता लेकिन मैंने 15-20 दिन पहले अखबार में एक खबर पढ़ी थी जिसको मैं मुख्य मंत्री जी के नोटिस में भी लाना चाहता हूं। डबल्यू जे०सी० कैनाल जो यमुनानगर, जगाधरी के आसपास से निकलती है, उसमें तेजाबी पानी डाला जाता है। उसके बारे में स्पीकर साहब, चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। करनाल की रिसर्च डेयरी के अंदर उस इलाके के किसानों की दूध की जांच की गई तो उस दूध में बी०एच०सी० और एल्ड्रिन और दूसरे इतने घातक तत्व पाए गए कि दूध का पीना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया। अगर इस तरह की चीजें उन नालों में या नहरों में डाली जाती हैं तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। यह तो एक छोटा सा परीक्षण ही हुआ है।

श्री बंसी लाल : इसी 31 मार्च तक इन समस्याओं का समाधान यमुना एक्शन प्लान में हो जाएगा। बाकी जो रह जाएंगी, उनको आगे कर देंगे।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि एन०डी०आर०आई० करनाल में केन्द्र ने यह परीक्षण किया और दूध भी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया। मेरी मुख्य मंत्री जी से गुजारिश है कि इन नहरों अथवा नालों में गन्दा पानी डाला जा रहा है कारखानों में ट्रीटमैंट प्लांट्स जानबूझ कर नहीं लगाए हुए हैं तथा इस प्रकार से पैसा बचाने के उद्देश्य से लोगों के स्वास्थ्य के

साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से आगरा कैनाल व गुड़गांव कैनाल भी बनी हुई हैं और इनको भी अगर देखा जाए तो वह भी अपने आप में एक मजाक है। वह नहर केवल नाममात्र की एक नहर है। स्पीकर साहब, वहां पर जब एस्टीमेट्स कमेटी गई तो उसने रिपोर्ट दी कि उसमें तीन चौथाई से ज्यादा गाद भरी हुई है, वह किसी ने नहीं निकाली है जो कि निकाली जानी चाहिए थी। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि पीछे जो हुआ सो हुआ, लेकिन वर्तमान में जिम्मेवारी आपकी सरकार की बनती है और आगरा कैनाल में जो तीन चौथाई से भी ज्यादा गाद भरी हुई है, वह केवल नाम की ही नहर दिखाई देती है, आज मेवात के लोगों की मांग है तथा मेवात के खेतों की आवश्यकता है कि उस नहर की गाद निकलवाकर के उस इलाके को पूरा पानी पहुंचाया जाए। इसलिए यह जो प्रस्ताव लाया गया है मैं एक बार फिर इसका समर्थन करते हुए यह चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी, हरियाणा की जनता की आवश्यकताओं से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, उनको उत्तर प्रदेश की सरकार, वहां के सांसदों या वहां के विधायकों के साथ सम्पर्क करके सुलझाने में कदापि संकोच न करें। हमारे प्रदेश की जनता, यहां के राजनीतिज्ञ, यहां का प्रशासन किसी भी बात में कहीं कमजोर नहीं है। इसलिए अपने हक को लेने के लिए , अपने दावे को मजबूत बनाने के लिए, अपना पक्ष रखें और पानी का फैसला कराएं जो आम जनता की आवश्यकता का मुद्दा है। इसको अमली-जामा पहनाएं। धन्यवाद।

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ माननीय सदस्यों के माध्यम से यह गैर सरकारी प्रस्ताव सदन में लाया गया है। मैं भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। इस विषय में एक बहुत बढ़िया प्वायंट है कि कुछ चैनल्ज और डिस्ट्रीबयूटरीज की गाद निकाल कर सफाई की गई है जिसके कारण हरियाणा प्रदेश की सिंचाई की क्षमता बढ़ी है लेकिन इसके साथ-साथ मेरी अपनी कुछ रिजर्वेशन हैं जो मैं सदन के समाने रखना चाहूंगा। सबसे पहली रिजर्वेशन तो यह है कि यह बहुत पुराना मुद्दा है शायद यह 35 या 40 साल पुराना मुद्दा हो लेकिन उस समय मुद्दा यह नहीं था कि आगरा कैनाल की सफाई की जाए मुद्दा यह था कि आगरा कैनाल हैड वर्कस पर हरियाणा सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। इस प्रस्ताव में उस मुद्दे को कहीं पर भी टच नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आगरा कैनाल के हैड वर्कस को अछूता बना दिया क्योंकि उसके एक किलोमीटर नजदीक तक हम चैनल्ज और डिस्ट्रीब्यूटरीज की सफाई भी नहीं कर सकते। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने एक सुझाव भी दिया था कि हम आगरा कैनाल के हैड वर्कस का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की बजाय कुछ अलग बात सोचे और वह यह कि उस नहर के पैरलल एक और नहर बनाई जाए और उस नहर के जरिए पानी लेकर आएं। उस मामले में मैं उतना जरूर कहना चाहूंगा कि उस समय मैं भी यहां पर बैठा था मुख्य मंत्री महोदय ने उनकी इस बात को बड़ी उत्सुकता से सुना और शायद मुख्यमंत्री जी उनकी इस बात को मानने के लिए ललायित भी हों लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि उसे दूसरी एस०वाई०एल० नहर न बना दें क्योंकि हरियाणा प्रदेश के हिस्से में एस०वाई०एल० नहर बना दो लेकिन पंजाब के हिस्से में एस०वाई०एल० नहर तैयार नहीं हो पाई। आप आगरा कैनाल के पैरलल कैनाल तो बना दें लेकिन यदि उसमें हमें पानी नहीं मिला तो उसके खर्चे का अन-नैसेसरी बर्डन प्रदेश पर पड़ेगा क्योंकि हमें आगरा कैनाल के हैड वर्कस के पास तक नहीं पहुचने दिया जाता। हैड वर्कस से एक किलोमीटर दूर तक हमें गाद भी नहीं निकालने दी जाती। अगर हम वहां पर उसके पैरलल कैनाल बनाएंगे तो उससे स्टेट एक्सचैकर पर खामखां बर्डन डालेंगे। एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने यू०पी० सरकार के साथ बातचीत करके उनको सिर्फ इस बात के लिए राजी किया है कि हरियाणा प्रदेश की टैरीटरी के अन्दर जो चैनल्ज हैं या

[डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत]

हरियाणा प्रदेश जिन चैनल्ज और जिन डिस्ट्रीब्यूटरीज के द्वारा पानी लेता है उनकी सफाई का काम हम अपने पैसे से कराएंगे जबकि उन डिस्ट्रीब्यूटरीज और चैनल्ज से जिस एरिया के अन्दर आबपाशी होती है उस एरिया का सारा का सारा आबियाना हमें यू०पी० सरकार को देना पड़ता है। यह समझौता भी गलत किया गया है। उन डिस्ट्रीब्यूटरीज और चैनल्ज की सफाई हम कराएंगे और उनसे सिंचित एरिया से जो आबियाना आएगा वह हम यू०पी० सरकार को दें तो यह बहुत बड़ी गलत बात है। अगर आबियाना यू०पी० सरकार को दें और उनकी सफाई हम अपने पैसे से कराएं तो यह प्रदेश के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। यह ठीक है कि एफीसिएंसी बढ़ी है सारी बात हुई लेकिन यह सारे का सारा खर्चे का बर्डन हम अपने ऊपर क्यों लें। हरियाणा सरकार को यू०पी० सरकार पर इस बात के लिए दबाब डालना चाहिए कि या तो आबियाना हम लेंगे या आप उन डिस्ट्रीब्यूटरीज और चैनल्ज की सफाई कराएं।

श्री बंसी लाल : अब आबियाना कोई भी नहीं ले रहा है। आबियाना न यू०पी० वाले ले रहे हैं और न हम ले रहे हैं।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अगर आप नहीं ले रहे तो अच्छी बात है लेकिन अभी तक उसका प्रोविजन नहीं हटाया गया है। यों तो कई लोग बिजली का बिल भी नहीं दे रहे है। आपने इस बारे में उनके साथ डिस्कस करके इस प्रोविजन को नहीं हटाया है। सरकार ने इस मुद्दे को उनके साथ टेकअप नहीं किया है। आप इस प्रोविजन को हटवाते। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि या तो उन एरियाज के किसानों का आबियाना माफ किया जाए या उन चैनल्ज और डिस्ट्रीब्यूटरीज की सफाई का पैसा यू०पी० सरकार से लिया जाए। इस प्रस्ताव में यह इश्यू भी होना चाहिए था। इसके अलावा कुछ और बातें भी सदन में आई। उन के मामले में मैं यह कहना चाहूंगा, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने भी बताया और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी बताया कुछ एरिया के अन्दर पैरलल चैनल बनाई हैं और हमने पानी की आवश्यकता को देखते हुए उनकी गाद निकाली है ताकि पानी की एफिशिएंसी बढ़ सके। हमारा पानी की सप्लाई का मेन मुद्दा है। हमारा यू०पी० सरकार के साथ काफी दिनों से इस नहर के पानी बारे डिफरेंस ऑफ ओपीनियन रहा है, हमारा मतभेद रहा है। हमारा मतभेद यह रहा है कि इस नहर का नियंत्रण हमारा न होने के कारण यू०पी० की सरकार हमें टाईमली पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दे रही इसीलिए हम इसका नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ताकि इस चैनल से जिस एरिया में पानी जाना है छोड़ा जा सके और उस एरिया को आवश्यकतानुसार पानी मिल सके। यह हमारे लिए एक अहम मुद्दा है। मेन बात तो पानी की रैगूलेशन की है। इसी प्रकार से यह बात केवल उस इलाके के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अन्दर पानी का रैगूलेशन परोपरली होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जिस एरिया में किसी मौके पर पानी की आवश्यकता नहीं होती तो उस वक्त वहां पर पानी बहुतायत में होता है और जब पानी की आवश्यकता होती है तो पानी नहीं मिलता। जैसा हमें बताया गया था कि रोहतक, सोनीपत, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, नारनौल आदि कई जिले मुश्किल से एक ही फसल ले पाते हैं। इसका कारण यह है कि इन एरियाज में पानी की एवेलिबिलिटी न होना है। क्योंकि जब पानी की जरूरत होती है तो पानी मिलता नहीं है। हमारे प्रदेश में ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा नीचे चला गया है और अधिकतर जगहों पर हमारे यहां नीचे खारा पानी है। अन्डर ग्राइंड वाटर खारी होने के कारण एक फसल भी हमको इस कीमत पर लेनी पड़ती है कि हम अपनी जमीन को रेह के अन्दर कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हमारी अच्छी खासी जमीन हैं उसके अन्दर हमें ब्रैकिश वाटर से इरीगेशन करनी पड़ती है। पानी की कमी में एक फसल लेने के लिए

हमारी अच्छी खासी उपजाऊ भूमि बर्बाद हो जाती है। इसलिए इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए कि बरसात के मौसम में जब पानी की जरूरत न हो तो तब तो इतना पानी दे दिया जाता है जिसकी कोई हद नहीं और उस वक्त हरेक किसान अपने खेत में मोघा छोड़ देता है ताकि उसके खेत में पानी खड़ा न रहे। इस प्रकार से वह पानी एक दूसरे खेतों में जाकर खड़ा हो जाता है जिस कारण पानी की निकासी न होने के कारण वहां पर खरपतवार भी खड़ी हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो पानी का रैगूलेशन है उसको ठीक किया जाये चाहे इसके लिए सरकार को हमारी कुछ कैनाल्ज को ड्रेनज के साथ कनैक्ट करना पड़े। हमें इस कैनाल का पानी ड्रेन्ज में डालकर उन इलाकों में पहुंचाना चाहिए जिन इलाकों में बारिश कम होती है, जहां इरीगेशन वाटर की फैसीलिटीज नहीं हैं, वहां पर ऐसे पानी की खपत की जा सकती है, लेकिन हमारी खेती को इसके लिए बर्बाद न होने दिया जाये यह भी एक अहम मुद्दा है, सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर बहुत सारे इलाके के अन्दर पीने के पानी की भी दिक्कत रहती है, जिस कारण लोग एक फसल ले पाते हैं। एक फसल ले पाने के कारण यही है कि पानी की पूरी अवेलेबिलिटी नहीं है। पिछली सरकार ने जो यमुना जल समझौता किया उसके तहत हमें जो पानी पहले मिलता था, उसको घटाया गया और हमारे हिस्से का पानी दूसरे प्रदेशों को दिया गया। उस वक्त हमारे मौजूदा मुख्य मंत्री जो अपोजीशन बैंचिज पर बैठते थे बड़े जोर शोर से इस इश्यू को उठाया था और कहते थे कि इस फैसले में कमी है, इसको ठीक कर देंगे। अब मुख्य मंत्री जी पहले वाले बदल गए हैं लेकिन हमारे यहां पर पानी की कमी अब भी बरकरार है। अब मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि वे पहले वाले फैसले को न माने, या फिर से उस प्वायंट को उठाया जाये और नए सिरे से बातचीत की जाये, यह भी एक बहुत जरूरी प्वायंट है। इस को दुबारा टेकअफ किया जाना चाहिए और यमुना जल समझौते को रद्द किया जाना चाहिए इसके अलावा एक बात और है, हमारा महेन्द्रगढ़ और गुड़गांव का इलाका, जिन इलाकों के अन्दर आगरा कैनाल से सिंचाई होती है, यहां के किसान गरीब हैं और इन इलाकों के अन्दर चौधरी देवी लाल की सरकार के वक्त बिजली के फ्लैट रेट् स रखे थे क्योंकि जैसा कि बताया गया है कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा हर फसल की इकोनामी निकाली गई है, उसकी आर्थिक दृष्टि यह पाई गई है कि किसान जितनी भी फसलें उगाता है अगर उसकी सब चीजों का हिसाब किताब लगाकर देखें तो किसान हर फसल के अन्दर घाटे में रहता है। इसलिए किसानों को सस्ती बिजली फ्लैट रेट पर देने की बात होनी चाहिए। अगर उससे बिजली की कोई कीमत वसूल नहीं की जाए तब भी किसान को घाटा रहता है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि किसानों को जो बिजली फ्लैट रेट पर दी जाती थी उस नीति को दोबारा से लागू किया जाना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर किसानों को पंजाब सरकार की तरह बिजली फ्री भी कर दी जाए तब भी उसको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा लेकिन उसको थोड़ी सी राहत जरूर मिल सकती है। हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां के 80 प्रतिशत लोग डायरैक्टलीऔर इनडायरैक्टली कृषि से जुड़े हुए हैं। यदि प्रदेश और किसान का हित चाहते हैं उसका विकास चाहते हैं तो आर्थिक रूप से किसान को ऊपर उठाया जाना चाहिए और उसको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिएं और इसके साथ ही किसान का आबियाना भी माफ किया जाना चाहिए और फसलों के अच्छे भाव भी उनको मुहैया करवाये जाने चाहिएं लेकिन यह ज्यादातर हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर किसानों को अधिक भाव सरकार नहीं दे सकती है तो कम से कम आबियाना और बिजली की सुविधा तो प्रदान कर ही सकती है (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरा निवेदन है कि हरियाणा के अन्दर कुछ एरिया में बिजली के फ्लैट रेट्स रखे गए थे उन इलाकों में पानी ज्यादा गहरा है और पानी को खींचने के लिए

[डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत]

ज्यादा बिजली की खपत होती है। इलाका रेतीला होने के कारण भी पानी की खपत भी ज्यादा होती है इसलिए सरकार द्वारा वहां पर सलैब्स बनाए हुए थे और फ्लैट रेट्स पर बिजली दी जा रही थी लेकिन उस सलैब प्रणाली को खत्म कर दिया है। उस एरिया के कष्टों और लोगों की आर्थिक दशा को देखते हुए इसको दोबारा से लागू करें। अगर हरियाणा सरकार बिजली चार्जिज और आबियाना को माफ कर देती है तो उससे भी उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार तो नहीं होगा लेकिन उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिलेगी इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि वह इस बारे सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री बलवंत सिंह (इसनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। यह जो प्रस्ताव आया है मैं इसका समर्थन करता हूं। आगरा कैनाल का कंट्रोल हरियाणा सरकार के पास आए मैं इसका समर्थन करता हूं और इससे सहमत हूं। हरियाणा प्रदेश को एक कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में जाना जाता है और यह प्रदेश कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं यह बात कहूंगा कि आगरा कैनाल का कंट्रोल और रख रखाव यू०पी० सरकार के पास है और इसके रख-रखाव और पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का काम हरियाणा सरकार को स्वयं अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि हरियाणा प्रदेश के मेवात और दूसरे इलाकों की पूरी तरह से सिंचाई हो सके। इसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को इस सदन में कहना चाहूंगा यह बात हरियाणा के हित की बात है इसलिए इसका कंट्रोल हरियाणा सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। स्पीकर साहब, इसी प्रकार से एस०वाई०एल० नहर की चर्चा बहुत पुरानी चलती आ रही है। चौधरी बंसी लाल जी जब पहले मुख्य मंत्री थे तब भी और उसके बाद भी जितने भी नेता आते हैं सभी हरियाणा प्रदेश के लिए एस०वाई०एल० की चर्चा जरूर करते हैं और उसे हल करने का आश्वासन भी देते हैं। चौधरी बंसी लाल जी की वर्तमान सरकार को बने हुए करीब 9 मास का समय हो गया है लेकिन उन्होंने अभी तक इस नहर का कोई भी कार्य नहीं किया है। हरियाणा प्रदेश को अगर इस नहर का पानी मिल जाएगा तो हरियाणा प्रदेश खुशहाल हो जाएगा। अगर यह पानी नहीं आया तो किसानों में खुशहाली नहीं आएगी। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक हरियाणा में कोई उद्योग धन्धे भी नहीं लगेंगे न पूरी बिजली मिल पाएगी और न ही दूसरी सुविधाएं ही मिल पाएंगी। कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में काफी कुछ कहा है इस सिलसिले में उपयोगिता इसलिए भी जरूरी है ताकि किसानों के खेत में पूरा पानी मिलता रहे। एक खुशहाल राज्य में उद्योग लगाए जाते हैं। हरियाणा का काफी एरिया दिल्ली के नजदीक लगता है। सैंट्रल गवर्नमैंट ने बाहर के उद्योगपतियों को भारतवर्ष में उद्योग लगाने के लिए कहा है। मिसाल के तौर पर दिल्ली के बाहर चाहे मेरा हल्का ले लो वहां पर कुछ फैक्टरियां लगी हुई हैं और वे फैक्ट्रियां किसानों की जमीन पर लगी हुई हैं। लेकिन जिन किसानों की जमीनों पर वे फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उन किसानों को उन से कोई फायदा नहीं है। उन फैक्ट्रियों से गंदा तेजाब वाला पानी निकलता है। सांपली में वह पानी खेतों में जाता है और वह खेतों को बर्बाद करता है। हमने कई बार उनको कहा है कि इस पानी को बंद करे लेकिन वे उस पानी को बंद नहीं करते हैं। इसके अलावा जिन किसानों की जमीन है उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है उनके बच्चों को उन फैक्ट्रियों में नहीं लगाया जा रहा है जब हम कहते हैं तो वे कहते हैं कि वे इन मशीनों को नहीं चला पाते हैं। जिस वजह से आज हरियाणा के बच्चों को वहां पर काम नहीं मिल पा रहा है। मैंने पिछली बार भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि आज हरियाणा के अंदर जो भी नई मशीनें आ रही हैं चाहे वे कम्प्यूटर चलाने के बारे में हैं ऐसे इन्स्टीच्यूट खोलने चाहिएं ताकि हमारे बच्चे वहां पर लेटेस्ट मशीनों को चलाना सीख सकें और उनको इन फैक्ट्रियों में काम मिल सके।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बलवन्त सिंह जी को बताना चाहूंगा कि गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के अन्दर 62 नए टैक्नीकल कोर्सिज शुरू किए हैं। हमने गुरू जम्भेश्वर के पूरे स्वरूप को टैक्नीकल कोर्सिज में बदल दिया है। (विघ्न)

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस देश की इक्नौमी कृषि पर टिकी हुई है इसलिए मैंने इस बारे में चर्चा की है। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से यह कह रहा था कि फैक्ट्रियों द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है इसकी रोकथाम के लिए कुछ करें।

श्री बंसी लाल : इस बारे में बहुत तेजी से कार्य चल रहा है।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन में भी मैंने यही बात उठाई थी कि यह सरकार फैक्टरी वालों को हिदायत दे कि वे वहां पर वहीं के लड़कों को लगाएं। उन्हीं को अपनी फैक्ट्री में नौकरी दें।

Mr. Speaker : Now the House is adjourned till 2.00 p.m., on Monday, the 10th March, 1997.

*13.30 hours (The Sabha then *adjourned till 2.00 p.m. on Monday, the 10th March, 1997).

28644–H.V.S.–H.G.P., Chd.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh * LIBRARY

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh